सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 156 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 21 मार्च 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

ईद मुबारक : राजधानी रायपुर, दुर्ग-भिलाई सहित प्रदेश के सभी जिलों में ईद का जश्न

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। माह-ए-रमजान के बाद चांद दिखते ही प्रदेश भर में ईद-उल-फित्र मनाई जा रही है। राजधानी रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में ईद का जश्न शुरू हो गया है। सुबह बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अता की। इस दौरान एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। इस दिन जकात और फित्रा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। जिससे जरूरतमंद लोग भी त्योहार की खुशियों में शामिल हो सकें। ईद के त्योहार को भाईचारे, खुशी और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है।

ईद के मौके पर दुर्ग भिलाई के तमाम मस्जिदों में शनिवार को नमाज अदा की। भिलाई के जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में लोग जुटे और नमाज अदा की। इसी प्रकार रायपुर में ईदगाह भाठा समेत तमाम मस्जिदों में नमाज़ियों ने ईद की नमाज अदा की। इसी तरह प्रदेश भर में ईद की नमाज अता की गई। कठिन रोजे के बाद ईद के दिन लोगों ने नमाज अदाकर देश-प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। लोगों ने सद्भावना के साथ ईद का जश्न मनाया। जनप्रतिनिधियों ने भी नमाज के बाद मुस्लिम भाईयों को ईद की मुबारक बाद दी।

सीएम विष्णुदेव साय व राज्यपाल रमेन डेका ने दी शुभकामनाएं

खास-खबर

रायपुर के मेटल पार्क में मिला नर कंकाल, जांच शुरू

रायपुर। राजधानी के उरला स्थित मेटल पार्क क्षेत्र में एक नर कंकाल मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां प्रारंभिक जांच में कंकाल की पहचान दिलीप नामक व्यक्ति के रूप में की गई है, जो करीब एक माह से लापता था। बताया जा रहा है कि मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई जा चुकी थी। ऐसे में कंकाल मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच, स्थानीय थाना पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है और आसपास के क्षेत्र में भी सुराग तलाशे जा रहे हैं।

केरल के कोच्चि में बंद कमरे से मिली 5 लाशें

कोच्चि। केरल के कोच्चि से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। शहर के वडुथला इलाके में एक किराए के मकान में एक ही परिवार के पांच लोग मृत पाए गए हैं। मृतकों में दो महिलाएं और तीन मासूम बच्चे शामिल हैं। शुरुआती जांच में पुलिस इसे सामूहिक आत्महत्या का मामला मान रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि पहले परिवार के बड़ों ने बच्चों की जान ली, इसके बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक, मृतक परिवार मूल रूप से तिरुवनंतपुरम का रहने वाला था। परिवार पिछले कुछ महीनों से वडुथला में एक किराए के मकान में रह रहा था। बताया जा रहा है कि वे परिवार के किसी सदस्य का पास के ही एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के सिलसिले में यहां आए थे।

जशपुर में बिजली गिरने से मजदूर की मौत

रायपुर। जशपुर जिले के दुलदुला में बिजली गिरने से मजदूर सनऊ राम (51) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 वर्षीय रेखा घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के बाद खतरे से बाहर बताया गया है। सनऊ अपने परिवार के साथ ईंट भट्ठे में मजदूरी के लिए आया था और अस्थायी मकान में रह रहा था। वह मूल रूप से सक्ती जिले के ग्राम डोमा का निवासी था।

छत्तीसगढ़ में अब घर-जमीन की रजिस्ट्री सस्ती सरकार ने खत्म किया 0.60 प्रतिशत उपकर

एक करोड़ की प्रॉपर्टी पर अब 60 हजार रुपए की सीधी बचत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अपना घर बनाने या जमीन खरीदने का सपना देख रहे मध्यमवर्गीय परिवारों और किसानों के लिए साय सरकार ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को विधानसभा ने 'छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026' को ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60 प्रतिशत सेस को खत्म कर दिया गया है। वाणिज्यिक कर मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश के आम नागरिकों, किसानों, मध्यमवर्गीय परिवारों तथा संपत्ति के क्रय-विक्रय से जुड़े लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ उपकर समाप्त होने से अब संपत्ति पंजीयन की लागत में कमी आएगी। उदाहरण के तौर पर एक करोड़ रुपये के बाजार मूल्य की संपत्ति पर नागरिकों को लगभग 60 हजार रुपये की सीधी बचत होगी। इससे जमीन-मकान की रजिस्ट्री अधिक सुलभ, सरल और कम खर्चीली बनेगी।

वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस फैसले से जनता पर पड़ने वाला सालाना 460 करोड़ का बोझ कम होगा। 2023 में पूर्व कांग्रेस सरकार ने 'छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन' और 'राजीव गांधी मितान क्लब' के संचालन के लिए स्टाम्प शुल्क पर 0.60 प्रतिशत सेस लगाया था। चौधरी ने कहा कि चूंकि अब 'मितान क्लब' अस्तित्व में नहीं है और रोजगार योजनाओं का खर्च सामान्य बजट से दिया जा रहा है, इसलिए जनता पर यह अनावश्यक बोझ लादे रखने का कोई औचित्य नहीं था।

स्मार्ट और पारदर्शी हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया: चौधरी

ओपी चौधरी ने बताया कि आम जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी। पंजीयन विभाग को अब 'वीजा ऑफिस' की तर्ज पर स्मार्ट बनाया जा रहा है। अब रजिस्ट्री होते ही बिना भटकते अपने आप नामांतरण हो जाएगा। अब तक 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला। सुगम एप के जरिए लोकेशन और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य हो गया है। इसी तरह 10 कार्यालयों को पीपीपी मोड पर वातानुकूलित और वाई-फाई युक्त बनाया जा रहा है।

छोटे जमीन मालिकों को 400 करोड़ तक लाभ

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गमीटर आधारित मूल्यांकन को खत्म कर फिर से हेक्टेयर दर लागू कर दी है। इससे छोटे जमीन मालिकों को 300 से 400 करोड़ रुपए का लाभ होगा। साथ ही, कृषि भूमि पर ढाई गुना मूल्यांकन और पेड़ों के अलग से मूल्यांकन जैसे जटिल नियमों को भी विदा कर दिया गया है। जमीन-मकान की रजिस्ट्री अधिक किफायती होगी।

लोगों को मिलेगी नागरिकों को बड़ी राहत : साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आम नागरिक, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। यह निर्णय केवल कर में राहत नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों के सपनों को सम्मान देने की दिशा में एक सार्थक पहल है, जो अपनी मेहनत की कमाई से घर और जमीन खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि आम नागरिक, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। इस कदम से संपत्ति के पंजीयन में वृद्धि होगी, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई ऊर्जा प्राप्त होगी।

रोड अंडरब्रिज के लिए होगी गर्डर लॉन्चिंग, दो दिन रद्द रहेंगी 6 ट्रेनें

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर मंडल के हथबंद-भाटापारा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण के लिए गर्डर डि-लॉन्चिग का काम चल रहा। बिलासपुर, रायपुर से इतवारी तक चलने वाली 22 मार्च को 6 और 23 मार्च को 2 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी।

वहीं गोंदिया-झारसुगड़ा-गोंदिया के बीच चलने वाली जेडी मेमू पैसेंजर 22 मार्च को आधे रास्ते ही चलेगी। अधोसंरचना विकास के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के हथबंद-भाटापारा सेक्शन के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 389 पर रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। उस रोड अंडरब्रिज निर्माण की अंतिम कड़ी में गार्डरों के डि-लॉन्चिग के लिए ट्रैफिक-सह पावर ब्लॉक लिया जा रहा है।

रद्द होने वाली गाड़ियां

- 22 मार्च को गाड़ी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
- 22 मार्च को गाड़ी संख्या 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
- 22 मार्च को गाड़ी संख्या 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
- 22 मार्च को गाड़ी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
- 22 मार्च को गाड़ी संख्या 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।
- 22 मार्च को गाड़ी संख्या 58205 रायपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर रद्द रहेगी।
- 23 मार्च को गाड़ी संख्या 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।
- 23 मार्च को गाड़ी संख्या 58202 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

दिव्यांग टीचर की हत्या के आरोपी ने लगाई फांसी, घर में लटकी मिली लाश

जमीन विवाद में की थी हत्या, ट्राईसाइकिल समेत जलाया था शव

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में दिव्यांग शिक्षक की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। जिस आरोपी टीमन लाल मनहर की पुलिस तलाश कर रही थी, वह अपने ही घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। इसके बाद पुलिस अब हत्या के साथ-साथ आरोपी की आत्महत्या के कारणों की भी जांच कर रही है। शुरुआती आशंका है कि गिरफ्तारी के डर से उसने यह कदम उठाया।

18 मार्च को जैजैपुर क्षेत्र के जर्वे गांव निवासी दिव्यांग शिक्षक देवानंद भारद्वाज की कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि टीमन लाल ने सिर पर कई वार कर हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया था। दोनों के बीच जमीन और पैसों को लेकर विवाद की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक ग्राम जर्वे के रहने वाले टीचर देवानंद भारद्वाज (42) ने टीमन लाल से जमीन खरीदने के लिए 7 लाख में सौदा किया था और पैसे भी दे दिए थे। पैसे देने के बावजूद टीमन ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई और ना ही पैसा वापस लौटाया। जब टीचर ने उससे अपने पैसे वापस मांगे तो हत्या कर दी।

गांव के कुएं में गिरे भालू का सफल रेस्क्यू, सीढ़ी के सहारे निकला बाहर

बालोद। जिले के डौंडी विकास खंड स्थित ग्राम जबकोहड़ा में शनिवार को एक जंगली भालू गहरे कुएं में गिर गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए भालू का सफल रेस्क्यू किया। दल्लीराजहरा वन परिक्षेत्र के अधिकारियों के अनुसार, भालू संभवत: पानी या भोजन की तलाश में बस्ती की ओर आया था और अंधेरे के कारण कुएं में गिर गया। बालोद उड़नदस्ता की टीम ने कुएं में एक लंबी सीढ़ी उतारी, जिसके सहारे भालू सुरक्षित बाहर निकलकर सीधे जंगल की ओर भाग गया। उप वनमंडलाधिकारी जीवन सिन्हा ने बताया कि भालू को बिना किसी नुकसान के उसके प्राकृतिक आवास में भेज दिया गया है। विभाग ने ग्रामीणों से वन्य प्राणियों को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ में बदला मौसम : आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का डबल अटैक, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अचानक बदले मौसम ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन साथ ही लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का असर साफ देखा जा रहा है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 20 मार्च को हुई तेज बारिश और ओलों ने मौसम के इस बदलाव को और स्पष्ट कर दिया।

मौसम विभाग ने स्थिति को गंभीर मानते हुए अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि कई इलाकों में तेज अंधड़, बिजली गिरने और ओले गिरने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा 21 मार्च को भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और आकाशीय बिजली का खतरा जारी रह सकता है। मौसम

वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदेश में एक साथ सक्रिय तीन अलग-अलग मौसमी सिस्टम इस बदलाव की वजह बने हैं। मध्यप्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती घेरा नमी को खींच रहा है, जबकि द्रोणिका रेखा पश्चिमी हिस्सों में अस्थिरता पैदा कर रही है। वहीं आंध्र प्रदेश के ऊपर सक्रिय ऊपरी हवा का चक्रवात बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रहा है, जिससे बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति बन रही है।

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने, बिजली गिरने की आशंका में पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है, क्योंकि ओलावृष्टि से नुकसान की आशंका बनी हुई है।

नेशनल हाइवे-49 बनेगा फोरलेन, बिलासपुर-रायगढ़ व ओडिशा की कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर के लिये खुशखबरी है। नगर के लिये बेहद महत्वपूर्ण नेशनल हाइवे एनएच-49 के बाकी हिस्से को फोरलेन बनाने के लिये पहल शुरू हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक मार्ग को उन्नत करने के लिए शहर के अकलतरा के तरौद चौक से रायगढ़ होते हुए ओडिशा सीमा तक फोरलेन मार्ग निर्माण की योजना बनाई है।

इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए मंत्रालय ने इंडियन टेक्नो कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया है। कंपनी ने भी तकनीकी सर्वे और डिजाइनिंग का कार्य शुरू कर दिया है। डीपीआर फाइनल होने के बाद निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।

155 किमी परियोजना को मंजूरी

राज्य सरकार ने ने 155 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसमें तरौद चौक अकलतरा से रायगढ़ तक 115 किलोमीटर और रायगढ़ से ओडिशा सीमा तक 40 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। परियोजना की अनुमानित लागत 1200 से 1500 करोड़ रुपये आंकी गई है।

अंतरराज्यीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार भी बढ़ेंगे

यह मार्ग औद्योगिक शहर रायगढ़ को ओडिशा से जोड़ेगा। फोरलेन बनने के बाद अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। परिवहन लागत में कमी आने से यह मार्ग क्षेत्रीय आर्थिक विकास का प्रमुख आधार सिद्ध होगा। वर्तमान में इस मार्ग पर टू-लेन सड़क होने की वजह से भारी वाहनों का अधिक दबाव रहता है। इस वजह से अक्सर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन फोरलेन बनने के बाद यातायात बेहतर होगा। वहीं यात्री कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। सबसे बड़ी और खास बात ये है कि इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सड़क किनारे विकसित होने वाली सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगी।

संपादकीय

सीवर में मौतें

बंद हो मैला सफाई की अमानवीय प्रथा

सदियों की लाचारी और समाज की संवेदनहीनता के चलते हाथ से सीवर की सफाई की अमानवीय प्रथा बदस्तूर जारी है। जारी ही नहीं है बल्कि मजबूर सफाई कर्मियों की मौत का सबब भी बनी हुई है। निश्चय ही यह घिनौनी प्रथा किसी भी सभ्य समाज के लिये एक कलंक के समान ही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हाथ से सीवर लाइन साफ करने की प्रथा मजबूर लोगों की लगातार जान ले रही है। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े इस समस्या के भयावह पक्ष को ही उजागर करते हैं। केंद्र सरकार की ओर बीते सप्ताह लोकसभा में बताया गया कि साल 2017 से अब तक देश में सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करते हुए 620 से अधिक सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है। कहना कठिन है कि ये आंकड़े वास्तविक हैं और सभी मौतों को देश में रिपोर्ट किया जा रहा है। ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में ठेकेदार दिहाड़ीदार सफाई कर्मियों की मौत को रफा-दफा करने का प्रयास करते हैं। कुछ चतुर-चालाक लोग परिजनों की मजबूरी को भांपते हुए छोटी-मोटी रकम देकर मामले पर पर्दा डाल देते हैं। ऐसे मामले शायद ही सामने आते हों कि सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद सफाईकर्मियों से सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई करवाने वाले ठेकेदार व स्थानीय निकाय के अधिकारियों को दंडित किया गया हो। क्या किसी लोकतांत्रिक समाज में किसी मजबूर सफाईकर्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है? निस्संदेह, लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े घोर लापरवाही को ही उजागर करते हैं। विडंबना यह भी है कि जहां करीब 539 परिवारों को पूरा मुआवजा मिला है, वहीं करीब 52 परिवारों को कोई पैसा नहीं मिला। निर्विवाद रूप से किसी मृत सफाई कर्मी के परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कोई दान नहीं है, बल्कि समाज का एक कानूनी और नैतिक दायित्व भी है। जब इस जरूरी सहायता में कोई कमी रह जाती है तो हमारी व्यवस्थागत उदासीनता ही उजागर होती है।

> “ केंद्र सरकार की ओर बीते सप्ताह लोकसभा में बताया गया कि साल 2017 से अब तक देश में सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करते हुए 620 से अधिक सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है। कहना कठिन है कि ये आंकड़े वास्तविक हैं और सभी मौतों को देश में रिपोर्ट किया जा रहा है। ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में ठेकेदार दिहाड़ीदार सफाई कर्मियों की मौत को रफा-दफा करने का प्रयास करते हैं।

निस्संदेह, यह कष्टकारी स्थिति साल 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर सवालिया निशान लगाती है। वहीं सरकारी दावा है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में किए गए एक सर्वेक्षण में देशभर के किसी भी जिले में हाथ से मैला साफ करने वाले सफाईकर्मी नहीं पाए गए हैं। सवाल ये है कि जब हाथ से सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी देश में नहीं हैं तो सीवर व सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के चपेट में आकर लोगों के मरने की खबरें कैसे आ रही हैं? यह दुखद ही है कि बीते मंगलवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक प्रमुख अस्पताल में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। सीवर-सेप्टिक टैंक की सफाई में मशीन के उपयोग को बढ़ावा देकर मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के उद्देश्य से ही सरकार द्वारा साल 2023-24 में शुरू की गई राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकीय तंत्र यानी नमस्ते परियोजना को अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने पिछले दिनों स्वीकार किया था कि मशीनीकरण के कारण दक्षता या सफाई व्यवस्था में सुधार के जरूरी संकेतक अभी तक पहचान में नहीं आए हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को पिछले वर्ष वेतन का भुगतान न होने, सुरक्षा उपकरणों की कमी और जाति आधारित भेदभाव को लेकर करीब 842 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जो इस बात का प्रमाण हैं कि समस्या की जड़ें बहुत गहरे रूप में विद्यमान हैं। हालांकि सरकारी दावा है कि सफाई का काम व्यवसाय पर आधारित है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सदियों से हाशिये पर पड़े समुदायों के श्रमिकों के बूते ही सफाई व्यवस्था चलायी जा रही है। निस्संदेह, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का दावा करने वाले समाज को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी नागरिक को अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। श्रम की गरिमा के सवाल का जबाव महज एक नारे से हासिल नहीं किया जा सकता। इसे एक जमीनी हकीकत बनाना होगा।

इच्छामृत्यु की अनुमति के बावजूद बाकी सवाल

प्रमोद जोशी

इच्छामृत्यु के विरोध में जो तर्क है, उसके अनुसार जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप गलत है। इच्छामृत्यु के अधिकार का दुरुपयोग होने का खतरा भी है। डॉक्टर 'किलर' बन जाएंगे। कोमा में पड़े लोगों को व्यर्थ समझ लिया जाएगा।

गाज़ियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परोक्ष इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) के लिए एम्स दिल्ली के पैलिएटिव केयर विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को पूरा होने में कई सप्ताह लग सकते हैं, क्योंकि इसमें कई चरण शामिल हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया की व्यावहारिकता से जुड़े कई सवाल अभी हैं, पर अब बहस एक्टिव इच्छामृत्यु यानी दवा देकर या किसी दूसरे तरीके से मृत्यु देने पर भी होगी। सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि संसद इस विषय पर कानून बनाए। 2018 और 2026 के फैसलों के बावजूद संसद ने अभी तक समग्र कानून नहीं बनाया। कोर्ट ने कई बार विधायिका से कानून बनाने की अपील की है।

पैलिएटिव केयर में ऐसी चिकित्सा देखभाल होती है, जिसका उद्देश्य गंभीर या असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीज को आराम देना और बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के बजाय मरीज के दर्द, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, बेचैनी या अन्य शारीरिक-मानसिक परेशानियों को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। सक्रिय इच्छामृत्यु मृत्यु का एक नया कारण उत्पन्न करती है; निष्क्रिय इच्छामृत्यु पहले से ही चल रही प्राकृतिक मृत्यु में बाधा को दूर करती है। एक मृत्यु का कारण बनती है; दूसरी मृत्यु को स्वाभाविक रूप से होने देती है। एक्टिव इच्छामृत्यु यानी दवा या किसी दूसरे तरीके से मौत देना पूरी तरह अवैध है।

प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीने के अधिकार' में 'गरिमापूर्ण मरने का अधिकार' शामिल है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने हां कहा है, लेकिन सीमित परिस्थितियों में। हरीश राणा केस के फैसले के बाद भी, यह बहस अभी अपूर्ण है। इच्छामृत्यु के विरोध में जो तर्क है, उसके अनुसार जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप गलत है। इच्छामृत्यु के अधिकार का दुरुपयोग होने का खतरा भी है। डॉक्टर 'किलर' बन जाएंगे। कोमा में पड़े लोगों को व्यर्थ समझ लिया जाएगा। कैथलिक चर्च, कई हिंदू संगठन और इस्लामी विद्वान इसे जीवन के खिलाफ मानते हैं।

यदि इसे लागू भी किया जाए, तो देश में अच्छी पैलिएटिव केयर बहुत कम है, इसलिए कई लोग इच्छामृत्यु को 'आखिरी विकल्प' मानते हैं। इस समय बहस का केंद्र बिंदु यही है कि पैसिव इच्छामृत्यु को और सुगम बनाया जाए या नहीं, जबकि एक्टिव इच्छामृत्यु को वैध करने की मांग अभी बहुत कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल असंभव रिकवरी वाले केस में, सख्त मेडिकल बोर्ड और न्यायिक देखरेख के साथ ही इसकी अनुमति देने पर विचार संभव है। बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि असली समाधान बेहतर पैलिएटिव केयर की व्यवस्था को मजबूत करने में है, न कि जल्दबाजी में एक्टिव इच्छामृत्यु को वैध करने में।

वर्ष 2013 में चंडीगढ़ में एक हादसे में चौथी मंजिल से गिरने के बाद से हरीश अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गत 11 मार्च को उनके मामले में, पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति देकर भारत में पहली बार इस अधिकार के व्यावहारिक इस्तेमाल की अनुमति दी है। अदालत ने 2018 में इसे संवैधानिक अधिकार मान लिया था।

हरीश राणा के माता-पिता की याचिका को, पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने और फिर उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। 2025 में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और यह निर्णय सुनाया। यह मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित और 2023 में सरलीकृत कानूनी ढांचे और इन दिशानिर्देशों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को उजागर करता है।

विशेषज्ञ सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच अंतर पर और भारत में मजबूत देखभाल अवसंरचना की आवश्यकता पर भी चर्चा करते हैं। जटिल समस्या यह नहीं है कि कानून किस बात की अनुमति देता है, बल्कि यह है कि रोगी, जब स्वयं बोलने में असमर्थ हो, तो कौन और किस आधार पर निर्णय कर सकता है। स्वस्थ दिमाग वाला वयस्क किसी भी चिकित्सा उपचार को अस्वीकार कर सकता है, और चिकित्सक को उस अस्वीकृति का सम्मान करना होता है। ज्यादा मुश्किल मामला अनैच्छिक मृत्यु का है। ऐसा रोगी जो स्थायी रूप से कोमा में है, जिसका अस्तित्व पूरी तरह से चिकित्सा तकनीक पर निर्भर है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की दो-न्यायाधीशों की पीठ के इस फैसले को पूरी तरह से समझने के लिए, 2011 में अरुणा शानबाग के मामले से लेकर 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में संवैधानिक फैसले तक की कड़ी को जोड़ना आवश्यक है। अरुणा रामचंद्र शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में नर्स थीं, जिनका 27 नवंबर, 1973 की रात को एक वार्ड अटेंडेंट ने गला घोंट दिया था। गला घुटने से उनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक गई थी। लगभग 42 वर्षों तक वे उसी अस्पताल में अचेत अवस्था में रहीं और 2015 में उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई।

2011 में, सर्वोच्च न्यायालय में उनकी जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की गई थी। दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में याचिका खारिज कर दी, लेकिन भारतीय कानून में पहली बार परोक्ष इच्छामृत्यु के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए। अदालत ने दयामृत्यु को अस्वीकार करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया कि मुंबई के केईएम अस्पताल की नर्सें और अन्य कर्मचारी अरुणा को मरने देना नहीं चाहते। इन नर्सों ने 37 साल से अरुणा की पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी। नर्सों के जीवन में अरुणा का एक मतलब हो गया था, जो उनकी एकता की कड़ी थी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2018 के फैसले में 2011 के फैसले की संरचनात्मक खामियों को उजागर किया। 2018 में कॉमन कॉज़ मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल है और असाध्य कोमा में पड़े रोगी के परिवार के सदस्य जीवन रक्षक उपचार बंद करने के लिए अदालत से अनुमति मांग सकते हैं। पीठ ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्धारित किए—दो स्वतंत्र चिकित्सा बोर्ड, परिवार की अनिवार्य सहमति और 30 दिन की पुनर्विचार अवधि—और अग्रिम चिकित्सा निर्देशों को मान्यता दी, जिनके द्वारा कोई व्यक्ति सक्षम रहते हुए भी अपने जीवन के अंतिम समय की प्राथमिकताओं को दर्ज कर सकता है।

राणा परिवार ने जब 2024 में अपने बेटे को जीवित रखने वाली फीडिंग ट्यूब हटाने की अनुमति मांगने के लिए पहली बार दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, तो अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, हरीश स्वतंत्र रूप से सांस लेकर बिना चिकित्सकीय सहायता के स्वयं को जीवित रख रहा है, इसलिए फीडिंग ट्यूब जीवन रक्षक प्रणाली को नहीं हटाया जा सकता। अब 11 मार्च के फैसले में इसे बदल दिया गया। न्यायालय ने अब यह माना है कि चिकित्सकीय सहायता प्राप्त पोषण को हटाना रोगी को भूखा रखना नहीं है। यह एक ऐसे हस्तक्षेप को हटाना है जिसका कोई चिकित्सीय उद्देश्य नहीं रह गया है।

शानबाग से लेकर कॉमन कॉज़ और हरीश राणा तक का सैद्धांतिक विकास 15 वर्षीय यात्रा है, जो कुछ नए सवाल खड़े कर रही है। 11 मार्च का फैसला सिद्धांत तो स्थापित कर देता है, जो विधि आयोग की 2006 की 196वीं रिपोर्ट में कानून की सिफारिश के बाद से ही अनसुलझा है।

लेखक वरिष्ठ संपादक रहे हैं।

परिपक्व संगठन हमेशा पूछते हैं कि 'क्या हो सकता है', न कि 'क्या हुआ'

एन. रघुरामन

जो गुड़ी पड़वा उत्सव का दिन होना था, वह इंदौर शहर के लिए शोक का दिन बन गया। बुधवार को एक घर में लगी आग में मारे गए सात लोगों की चिताएं जब एक साथ जलीं तो इसकी पीड़ा पूरे शहर को सामूहिक तौर पर महसूस हुई। मृतकों में एक मासूम भी था।

इस दर्दनाक हादसे के दिन मध्यप्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपम राजन ने कहा कि 'राज्य का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। हम आईआईटी और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से एक व्यापक फॉरेंसिक जांच करेंगे। ईवी विशेषज्ञों की बैठक भी बुलाई जाएगी, ताकि समझा जा सके कि चार्जिंग के दौरान ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसके पीछे कौन-सी विशेष तकनीकी खामियां हैं।'

ऐसे बयान सोचने को मजबूर करते हैं कि क्यों अधिकतर संगठन शायद ही कभी इस पर चर्चा करते हैं कि 'क्या हो सकता है' और वे 'क्या व क्यों हुआ' पर ही क्यों अधिक ध्यान देते हैं। ज्यादातर बैठकों के एजेंडा में राजस्व अनुमान और उन्हें हासिल करने के तरीके, ऑपरेशनल टारगेट्स और उन्हें बढ़ाने के उपाय, एक्सपांशन प्लान्स और प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करने की रणनीति को ही शामिल किया जाता है। और आखिर में सेल्स डिपार्टमेंट के वेंडर नेगोशिएशन, जहां चर्चा होती है कि उन्हें कम मार्जिन पर कैसे राजी करें।

अधिकतर बैठकों में एक पैमाने पर चर्चा छूट जाती है, वह है 'जोखिम'। कड़वी सच्चाई है कि ज्यादातर संगठन जोखिम के बजाय मुनाफे पर बारीकी से नजर रखते हैं और मैनेजमेंट की भाषा में इसे 'खतरनाक असंतुलन' कहा जाता है।

एक बोर्डरूम की कल्पना कीजिए, जहां शीर्ष नेतृत्व बैठा है और अचानक टीम मेम्बर्स से पूछता है कि 'इस तिमाही के लीडिंग सेफ्टी इंडिकेटर्स क्या हैं?' यकीन मानिए, चंद पलों के लिए कमरे में सन्नाटा पसर जाएगा। चूंकि जवाब तो देना है तो कोई कहेगा कि 'सर, हम सेफ्टी कंप्लायंट हैं'।

दूसरे कहेंगे 'सर, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।' लेकिन यह तो लीडर का सवाल था ही नहीं। उसने पिछली घटनाओं के बारे में नहीं, बल्कि भविष्य के जोखिमों के बारे में पूछा था। अच्छे संगठन आम तौर पर यह आकलन करते हैं कि क्या हो सकता है और उसे कैसे टाल सकते हैं।

मसलन, गर्मियों में बिजली बोर्ड की बैठकों में शहर में संभावित जोखिम और उसे टालने के उपायों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अकसर बिजली बोर्ड आपदा आने के बाद उससे निपटने वाले फायरफाइटर्स की तैयारियां करता है।

सेफ्टी मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं। 1. लैगिंग इंडिकेटर्स : इसमें घटनाओं की संख्या, मौत और घायलों की संख्या और अंतिम नुकसान शामिल होता है। 2. लीडिंग इंडिकेटर्स : यह खतरों की पहचान, सामने आई छोटी-सी चूकें, सेफ्टी ऑडिट्स की संख्या, सेफ्टी ट्रेनिंग का समय और अंतत: ड्रिल परफॉर्मेंस के अंकों की बात करता है।

अधिकतर परिपक्व संगठन महज हादसों को नहीं मापते, क्योंकि वह तो विफलताओं का रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम जैसा है। वे हमेशा अपने सिस्टम की ताकत मापते हैं, क्योंकि इसी से रोकथाम की क्षमता आंकी जा सकती है। वे रिव्यू मैकेनिज्म बनाते हैं, कठिन सवाल पूछते हैं और उस चीज को मापते हैं, जो कीमत चुकाए जाने से पहले सच में मायने रखती है।

अगर नेतृत्व 'सिस्टम हेल्थ' की नियमित समीक्षा नहीं करता तो जोखिम चुपचाप बढ़ता रहता है और अंतत: एक दिन पूरा सिस्टम ढह जाता है। ऐसी घटनाएं पूर्व चेतावनी नहीं देतीं, बल्कि सीधे सुर्खियां बनती हैं। लैगिंग सेफ्टी मैट्रिक्स हमें केवल नुकसान बताते हैं, जबकि लीडिंग सेफ्टी मैट्रिक्स बताते हैं कि क्या करना चाहिए।

देशभर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए यह और जरूरी हो जाता है। याद रखिए, रिस्क एक्सपोजर बड़ा वित्तीय जोखिम भी है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेफ्टी मैट्रिक्स की समीक्षा उतनी ही गंभीरता से करनी चाहिए, जितनी फाइनेंशियल मैट्रिक्स की होती है।

फंडा यह है कि सुरक्षा सिर्फ ऑपरेशनल टॉपिक नहीं, एक रणनीति भी है। इसलिए परिपक्व संगठनों का नारा होना चाहिए कि 'सुरक्षा बोर्डरूम की चर्चा का विषय है।' सुरक्षा किसी एक डिपार्टमेंट का अपडेट भर नहीं, बल्कि समूचे शासन की जिम्मेदारी है।

पानी से जुड़ा लैंगिक समानता का मुद्दा

दीपक कुमार शर्मा

पानी और समानता को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। जहां पानी सुरक्षित, सुलभ और समान रूप से उपलब्ध होगा, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय मजबूत होंगे। जल दिवस याद दिलाता है कि जल संकट का समाधान तभी टिकाऊ होगा, जब उसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों की समान भागीदारी होगी।

पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की रीढ़ भी है। खेती, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जीवन, सब कुछ पानी पर निर्भर है। इसके बावजूद आज दुनिया गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। यह संकट केवल पानी की कमी का नहीं, बल्कि उसके असमान वितरण, प्रबंधन की विफलता और सामाजिक असंतुलन का भी है। इसी बारे में चेतना जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाता है।

विश्व जल दिवस की शुरुआत 1993 में हुई थी, जब महसूस किया गया कि पानी से जुड़ी समस्याओं को केवल तकनीकी या स्थानीय मुद्दा मानकर नहीं सुलझाया जा सकता। यह एक वैश्विक चुनौती है, जिसका समाधान सामूहिक जिम्मेदारी से संभव है। हर वर्ष एक विशेष विषय चुनकर पानी के किसी एक पहलू पर फोकस किया जाता है, ताकि नीति निर्धारकों व नागरिकों को स्पष्ट दिशा मिल सके। वर्ष 2026 के लिए विश्व जल दिवस की थीम है पानी और लैंगिक समानता। इसका संदेश है जहां पानी बहता है, वहां समानता बढ़ती है। जल संकट का प्रभाव सभी पर समान नहीं पड़ता। समाज के कुछ वर्ग खासकर महिलाएं व लड़कियां, पानी की कमी और खराब जल प्रबंधन से अधिक प्रभावित होती हैं।

दुनिया के अनेक हिस्सों में घर के लिए पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-दूर से पानी लाना सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में उनका समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य तीनों प्रभावित होते हैं। जब कोई लड़की रोज कई घंटे पानी लाने में लगाती है, तो उसका स्कूल जाना बाधित होता है। जब कोई महिला भारी बर्तन उठाकर लंबी दूरी तय करती है, तो उसका स्वास्थ्य कमजोर होता है। यहां प्रश्न केवल पानी उपलब्ध होने या न होने का नहीं है, बल्कि यह है कि पानी की कमी किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आंकड़े बताते हैं कि पेयजल की सुविधाओं की कमी का सबसे अधिक बोझ महिलाओं पर पड़ता है। विश्व जल दिवस 2026 की थीम जोर देती है कि पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए महिलाओं को जल प्रबंधन, योजना निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना जरूरी है। अनुभव बताता है कि जहां स्थानीय जल समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, वहां जल स्रोतों का रखरखाव बेहतर हुआ और जल उपयोग अधिक जिम्मेदारी से किया गया।

भारत जैसे देश में यह विषय और अधिक प्रासंगिक है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, वहीं यहां क्षेत्रीय जल असमानता बहुत गहरी है। कहीं बाढ़ की समस्या, तो कहीं सूखा। दोनों ही स्थितियों में महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने भारत में हर घर नल से जल पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे कई क्षेत्रों में महिलाओं का समय बचा है, जिसे वे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में लगा पा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि जब पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, तो समानता की दिशा में भी ठोस प्रगति होती है।

पानी को यदि केवल संसाधन मानकर देखा जाएगा, तो समाधान भी सीमित रहेंगे। लेकिन जब पानी को मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तब नीतियां अधिक समावेशी बनती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है। यानी समाज में पानी की उपलब्धता केवल सुविधा नहीं, बल्कि अधिकार है, और इस अधिकार से किसी भी वर्ग को वंचित नहीं किया जा सकता।

लैंगिक समानता के बारे में जरूरी है कि जल क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व के मौके मिलें। इंजीनियरिंग, योजना निर्माण, प्रशासन और निगरानी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से जल प्रबंधन अधिक संवेदनशील व व्यावहारिक बनेगा। महिलाएं जल संकट को केवल आंकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि रोजमर्रा जीवन के अनुभव के रूप में समझती हैं। यही अनुभव नीतियों को जमीन से जोड़ता है।

विश्व जल दिवस 2026 सोचने पर मजबूर करता है कि जल संकट का हल केवल पाइपलाइन, टंकी या परियोजनाओं से नहीं होगा। इसके लिए सामाजिक सोच में बदलाव जरूरी है। जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा कि पानी की कमी असमानता पैदा करती है, तब तक समाधान अधूरा रहेगा। समानता का अर्थ सिर्फ अधिकार देना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और निर्णय में भागीदारी भी है। पानी का विवेकपूर्ण उपयोग, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों की रक्षा और समाज में जागरूकता फैलाना, ये सभी कदम समानता में योगदान देते हैं।

विश्व जल दिवस 2026 का संदेश अत्यंत स्पष्ट और दूरगामी है। पानी और समानता को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। जहां पानी सुरक्षित, सुलभ और समान रूप से उपलब्ध होगा, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय मजबूत होंगे। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि जल संकट का समाधान तभी टिकाऊ होगा, जब उसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों की समान भागीदारी होगी। जहां पानी बहता है, वहीं एक न्यायपूर्ण और समानता वाले समाज की नींव मजबूत होती है।

आखिर एक ही सवाल के कितने जवाब

सरकार कह रही है कि गैस है। गैस की कोई कमी नहीं है। और आप तो जानते हैं कि सरकारी बयानों में किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होती। होती है क्या? सवाल यह था, बल्कि है भी कि गैस है क्या? यह सवाल किसी डॉक्टर ने मरीज से नहीं पूछा और किसी मरीज ने डॉक्टर से भी नहीं पूछा। जी हां, गैस एक बीमारी भी है। यह पेट में रहे तो अफारा आ जाता है, दिल के आसपास हो तो हृदयघात का डर सताने लगता है। और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि यह सिर चढ़कर भी बोलती है-गरूर की तरह से।

एक गैस वह भी होती है जो फैक्टरियों-कारखानों वगैरह से गफलत में रिस जाती है और न जाने कितने ही लोगों की जान ले लेती है। भोपाल में तो इसने हजारों लोगों की जान ले ली थी, लेकिन दो-चार-दस लोगों की जान तो छोटी-मोटी फैक्टरियों से रिसने वाली गैस भी ले ही लेती है। मजदूरों तथा यूनियनों का तो बल्कि यह आरोप होता है कि यह गफलत उतनी नहीं होती, जितनी सुरक्षा में चूक होती है। फिर एक गैस गटर की होती है। नहीं वो वाली नहीं, जिसकी आजकल बड़ी चर्चा है और जिस पर मीम वगैरह न जाने क्या-क्या बन रहे हैं। बल्कि अब तो वह राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का भी एक रूप हो ली है।

खैर, हम गटर की उस जहरीली गैस की बात कर रहे हैं, जिससे गटर की सफाई करते हुए न जाने कितने सफाईकर्मी अपनी जानें गवां चुके हैं। लेकिन इनमें से किसी गैस का अभी कोई जिक्र नहीं है। अभी तो जो यह सवाल पूछा जा रहा है कि गैस है क्या, यह उस गैस के लिए पूछा जा रहा है, जिससे खाना बनता है। वैसे खाना गोबर गैस से भी बनता है। पर अभी उसका भी कोई जिक्र नहीं है। बल्कि उसे तो इस लायक भी नहीं माना जा रहा उसे नाले की गैस जितना भी महत्व दिया जा सके। तो यह जो खाना पकाने वाली गैस है और जो सिलेंडर में भरकर आती है, सवाल उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि गैस है क्या?

हालांकि, इस सवाल में सरकार विरोधी होने से लेकर देशद्रोही होने तक की अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है। इस सवाल के उठते ही गृहस्थिने घबरा उठी हैं और गृहस्थ सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों और डिपुओं की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रेस्तरां वाले कह रहे हैं कि गैस नहीं है। नहीं वे वैसे नहीं कह रहे हैं जैसे राशन डिपोवाला कह देता है कि राशन नहीं है। उसे तो राशन ब्लैक करना होता है न। रेस्तरां वाले को खाना ब्लैक थोड़े ही करना है। बल्कि अब तो सिलेंडर ब्लैक करने वाला भी कह रहा है कि गैस नहीं है। हालांकि, जिस जमाने में सिनेमा के टिकट ब्लैक में बिकते थे, तब किसी भी ब्लैकिए ने यह नहीं कहा कि टिकट नहीं है।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
छत्तीसगढ़

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ पर पेंटिंग बनाएंगे राज्य के सुप्रसिद्ध चित्रकार

भिलाई। नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ विषय पर पेंटिंग बनाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य के सुविख्यात चित्रकारगण। उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास में मिलने आए कलाकारों को उनके सामाजिक कार्यों के लिए साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के हिंसक कार्यों को बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे भारत में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि उनके कारण छत्तीसगढ़ ने क्या नहीं खोया है। इस दौरान ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के सदस्य डॉ. अंकुश देवांगन, सुप्रसिद्ध चित्रकार रोहिणी पाटणकर, प्रवीण कालमेघ, गुंजन शर्मा तथा तरुण धोटे उपस्थित थे।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों के हिंसक उत्पातों को कैनवास में प्रदर्शित करना प्रासंगिक है जिससे जनसमूह में सत्य का उद्गार होगा। इससे पूरी दुनिया में भी संदेश जाएगा कि बंदूक से किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। मुलाकात के दौरान रोहिणी पाटणकर, गुंजन शर्मा और प्रवीण कालमेघ ने गृहमंत्री को बताया कि नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ विषय पर पेंटिंग बनाने के लिए खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, कोंडागांव, रायपुर, बस्तर तथा दुर्ग, भिलाई के समस्त कलाकार उत्सुक हैं। वहीं प्रख्यात मॉडर्न आर्ट चित्रकार डी.एस. विद्यार्थी, बी.एल. सोनी, मशहूर मूर्तिकार मोहन बराल, मीना देवांगन एवं साहित्यकार मेनका वर्मा ने जानकारी दी है कि इस वर्कशॉप की ऐसी तैयारी हो रही है कि दर्शक लंबे समय तक याद रखेंगे। चर्चा में गृहमंत्री ने अंकुश देवांगन द्वारा लगभग छत्तीस वर्षों से छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को निशुल्क कला सीखाए जाने की मुक्तकंठ प्रशंसा की।

भिलाई में हिंदू नववर्ष पर भव्य आयोजन, जोर-शोर से तैयारी, सेक्टर-9 चौक बनेगा आस्था का केंद्र

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। हिंदू नववर्ष 2083 के स्वागत को लेकर भिलाई में आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। सेक्टर-9 चौक पर विशाल ध्वजारोहण, सामूहिक हनुमान चालीसा और भव्य महाआरती के साथ ऐसा आयोजन होने जा रहा है, जो पूरे शहर को आध्यात्मिक रंग में रंग देगा।

श्रीराम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। शाम 4 बजे से शुरू होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है।

आयोजन स्थल को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है, ताकि नववर्ष का स्वागत पूरी भव्यता और श्रद्धा के साथ किया जा सके। पर्व को बेहतरीन ढंग से मनाने के लिए शहर में हलचल तेज हो गई है।

समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पाण्डेय ने बताया कि हिंदू नववर्ष केवल तिथि परिवर्तन नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण और सामूहिक हनुमान चालीसा के माध्यम से लोगों में एकता, ऊर्जा और धार्मिक जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को भी अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने नगरवासियों, विशेषकर युवाओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाएं।

भिलाई में होने वाला यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनने जा रहा है, जो नववर्ष के साथ नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संदेश देगा।

नसबंदी के दौरान हुई मौत, फ्रीजर कॉफिन खराब, दवा खरीदी में घोटाला, तो सही क्या?

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। दुर्ग शहर के स्वास्थ्य विभाग में लगातार सामने आ रही लापरवाही एवं अनियमितताओं के खिलाफ शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर त्वरित जांच एवं कड़ी कार्यवाही की मांग की।

ज्ञापन में उन्होंने बताया कि नसबंदी ऑपरेशन के दौरान हुई महिलाओं की मृत्यु के मामले में आज तक न तो वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाया है और न ही कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। शासन द्वारा निर्धारित 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि आज तक पीड़ित परिवारों को नहीं दी गई है, साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि ऑपरेशन में प्रयुक्त दवाइयों की खरीदी सीजीएमएससी के माध्यम से न होकर अन्य स्रोतों से किए जाने की जानकारी सामने आई है। यदि दवाइयाँ अमानक थीं, तो अब तक दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

धीरज बाकलीवाल ने कहा कि जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी के बावजूद चिकित्सकों को सीएमएचओ कार्यालय में अटैच किया जाना गंभीर लापरवाही है, जिससे आम मरीजों को उपचार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने आरबीएसके टीम को एम्बुलेंस से भेजे जाने, दवाइयों की कमी तथा जांच व्यवस्था के केवल कागजों में सीमित रहने जैसे मुद्दों को भी उठाया।

उन्होंने बताया कि दुर्ग के मर्चूरी का फ्रीजर पिछले 6 माह से खराब पड़ा है जिसके कारण शहरवासियों को परेशानी हो रही है। नया फ्रीजर एवं अन्य व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही केवल कागजों पर चल रही है वही मेडिकल मोबाइल यूनिट में दवाइयों की कमी, ट्रामा यूनिट निर्माण की धीमी गति जैसी समस्याओं को भी ज्ञापन में शामिल किया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि जिले में टीबी मरीजों की जांच अधूरी है तथा थायराइड, बीपी एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के प्रति भी लापरवाही बरती जा रही है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है।

धीरज बाकलीवाल ने प्रशासन से सभी मामलों की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी जनहित में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले, दीपक दुबे, रायसिंह ढिकोला, प्रेमलता साहू, दुष्यंत देवांगन, केके सिंह, सुरेंद्र राजपूत, जमुना साहू, पोषण साहू, आनंद ताम्रकार, राहुल शर्मा, मुकेश साहू, अनूप वर्मा, ओमप्रकाश जोशी, बिजेंद्र भारद्वाज, भीम सेन, खुर्शीद अहमद, मनीषा सोनी, संजय बत्रा, दुष्यंत साहू, आदित्य नारंग, चंद्रशेखर पारख, दीपक जैन,अनिल राव, राकेश यादव, प्रीतम देशमुख, कुंदन सोनी, अंश चतुर्वेदी, अमित मिश्रा सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे।

सीलिंग टीम के पहुंचते ही पंजाब बार मालिक ने चुकाया पूरा बकाया

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आज आयुक्त सुमित अग्रवाल के सख्त निर्देश पर नगर निगम की लाइसेंस शाखा एवं राजस्व विभाग की टीम न्यू बस स्टैंड स्थित पंजाब बार को सीलबंद करने पहुंची। निगम की सख्ती के मद्देनजर हड़कंप मच गया और सीलबंदी की कार्रवाई से बचने के लिए उसने तत्काल पांच वर्षों का लंबित अनुज्ञा शुल्क, 2 लाख 25 हजार रुपये, मौके पर ही जमा कर दिया। पंजाब बार पिछले पांच वर्षों से अनुज्ञा शुल्क नहीं दे रहा था। नगर निगम ने तीन बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन संचालक की ओर से न तो कोई जवाब दिया गया और न ही शुल्क जमा करने की पहल की गई।

डॉ. परदेशीराम वर्मा की कहानियों का हो रहा रूसी, अंग्रेजी और उर्दू अनुवाद

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सुप्रसिद्ध साहित्यकार, छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निवासी डॉ. परदेशी राम वर्मा की कहानियों का रूसी, अंग्रेजी और उर्दू में अनुवाद हो रहा है। यह अनुवाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि डॉ. वर्मा को हिन्दी के विद्यार्थियों के बीच अपनी कहानियों पर व्याख्यान के लिए इस महीने की पंद्रह और सोलह तारीख को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया था, जहाँ उन्हें 'लेखक से मिलिए 'कार्यक्रम में विद्यार्थियों और फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और उर्दू के शोधार्थियों के बीच जाकर अपनी कहानियों पर बात करने और उनसे भी बहुत कुछ जानने -सीखने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी कहानियों के रूसी, अंग्रेजी और उर्दू अनुवाद के सन्दर्भ में हिन्दी के विद्यार्थियों के बीच व्याख्यान दिया। उनकी अधिकांश कहानियाँ छत्तीसगढ़ की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित हैं।

डॉ. परदेशीराम वर्मा ने विश्वविद्यालय के लोहित छात्रावास में विद्यार्थियों से मुलाकात की। विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रोफेसर डॉ. मलखान सिंह ने पहले दिन के आयोजन में डॉ. परदेशी राम वर्मा द्वारा सम्पादित पत्रिका 'नव आगमन' के संत कवि पवन दीवान पर केंद्रित विशेषांक का विमोचन किया।

आधा साल बीता, जीपीएफ का पता नहीं

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा।

जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित 128 आवेदन प्राप्त हुए।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्राप्त अनेक आवेदनों पर त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर प्रकरणों की जानकारी ली और तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में चंदखुरी ग्राम के वार्ड क्रमांक 6 एवं 7 के निवासियों ने हर घर नल-जल योजना के तहत पाइप-लाइन कार्य न होने पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि अमृत मिशन योजना के तहत गांव के कई वार्डों में पाइप-लाइन बिछाकर घर-घर कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके वार्ड को अब तक इस योजना से वंचित रखा गया है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिससे उन्हें आस-पास के वार्डों से पानी लाना पड़ता है। इस पर कलेक्टर ने पीएचई विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

अप्रैल के पहले सप्ताह में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग तथा क्रिश्चन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी दुर्ग के संयुक्त तत्वावधान में अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम क्रिश्चन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी के परिसर में आयोजित किया जाएगा।

जिला रोजगार कार्यालय के उपसंचालक ने बताया कि निजी क्षेत्र के ऐसे नियोक्ता जो अपने संस्थानों में रिक्त पदों की भर्ती इस मेले के माध्यम से करना चाहते हैं, वे अपनी रिक्तियों की जानकारी छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग के ई-रोजगार पोर्टल के जरिए जिला रोजगार कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं।

पोर्टल में रिक्तियां अधिसूचित करने के लिए नियोक्ताओं को रोजगार मेला हेतु पंजीयन अनिवार्य होगा। पंजीयन के लिए नियोक्ता के पास जीएसटी होना आवश्यक है तथा संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इस मेले का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना और नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल उपलब्ध कराना है। अधिक जानकारी के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में संपर्क कर सकते हैं।

इंदिरा मार्केट के बंद कुएं में कचरा फेंकने पर होगी कार्रवाई

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम द्वारा शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार सख्ती बरती जा रही है। इंदिरा मार्केट स्थित निगम द्वारा किये गए इंदिरा मार्केट सौंदर्यकरण कुएं में कचरा फेंकने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। कुआं चौक के आसपास रहने वाले नागरिकों द्वारा नगर निगम प्रशासन को शिकायत दी गई थी कि बंद कुएं में लगातार कचरा डाला जा रहा है। जिससे गंदगी फैलने के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं।

शिकायत मिलने पर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल टीम मौके पर भेजी और कुएं की साफ-सफाई करवाई गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति कुएं में कचरा डालते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफसख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुएं को ढंक दिया गया है, लेकिन उसमें लगी जाली का एक हिस्सा खुला होने के कारण लोग उसमें कचरा डाल रहे हैं।

आयुक्त ने आसपास के दुकानदारों एवं ठेला-खोमचा संचालकों से अपील की है कि वे शहर की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें और कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, दुर्ग के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा।

फेडरेशन के प्रमुख सलाहकार एवं संभागीय संयोजक राजेश चटर्जी, जिला संयोजक विजय लहरे, महासचिव अनुरूप साहू, जिला मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव सहित विभिन्न विभागों और संगठनों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने रैली में भाग लिया।

रैली के माध्यम से कर्मचारियों ने सरकार से लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। ज्ञापन में प्रमुख रूप से जुलाई 2016 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, 8, 16, 24 और 32 वर्षों में समयमान वेतनमान देने तथा अर्जित अवकाश नगदीकरण को 300 दिवस तक किए जाने की मांग शामिल है। विभिन्न विभागों में वेतन विसंगतियों को दूर करने, शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ देने, सहायक शिक्षकों एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने, अनुकंपा नियुक्ति की वर्तमान सीमा समाप्त करने और पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग की है।

भाजपा की रीति-नीति से अवगत कराने प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग महा अभियान 2026 के अंतर्गत दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में मंडल स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इस कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मध्य मंडल एवं कसारीडीह-बोरसी मंडल का प्रशिक्षण वर्ग अग्रसेन भवन में संपन्न हुआ।

सात सत्रों में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में विभिन्न विषयों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं दुर्ग संभाग प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही, जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य चंद्रिका चंद्राकर, जिला महामंत्री दिलीप साहू, विनोद अरोरा, उपाध्यक्ष शिवेंद्र परिहार एवं राजीव पांडेय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य अतिथि जगन्नाथ पाणिग्रही ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अनुशासित बनाना और संगठन की नीति-रीति से अवगत कराना प्रशिक्षण वर्ग का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा की वास्तविक ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो संगठन की विचारधारा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।

स्वदेशी मेला में शामिल हुए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर

दुर्ग। गत दिवस, जयंती स्टेडियम, भिलाई में आयोजित स्वदेशी मेला 2026 में दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर सम्मिलित हुए और स्वदेशी उत्पादों का आनंद लेते हुए मेले की विविध गतिविधियों का अवलोकन किया। विधायक ने प्रदर्शित स्टालों का सघन निरीक्षण किया, उद्यमियों-कलाकारों से संवाद कर उनके नवाचारों और उत्पादों की जानकारी ली तथा स्वदेशी को अपनाने के संकल्प को दोहराया। श्री चंद्राकर ने कहा, स्वदेशी केवल वस्तु नहीं, आत्मनिर्भरता का विचार है। जयंती स्टेडियम का यह मंच हमारे स्थानीय कारीगरों, महिला स्व-सहायता समूहों, स्टार्ट-अप्स और पारंपरिक शिल्पियों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ता है। यहाँ की गुणवत्ता, विविधता और प्रस्तुति देखकर गर्व होता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करता हूँ कि 'वोकल फॉर लोकल' को व्यवहार में लाएँ—स्थानीय उत्पाद खरीदें, अपने उद्यमियों को सशक्त करें। उन्होंने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के मेलों से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, बल्कि युवा उद्यमियों को मंच, प्रशिक्षण और बाजार भी मिलता है।

हरी नगर क्षेत्र में टुल्लू पम्प से बिगड़े हालात, निगम हुआ सख्त

- जल संकट समाधान के लिए निगम सक्रिय, नलों में टोटी लगाने और पाइपलाइन विस्तार पर जोर
- अवैध पानी खींचने पर कड़ी कार्रवाई, कनेक्शन काटने और जुर्माने की चेतावनी

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 59 हरी नगर में जल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए महापौर अलका बाघमार द्वारा जल कार्य प्रभारी लीना दिनेश देवांगन,देवनारायण चंद्रकार, ज्ञानेश्वर ताम्रकर, पार्षद गोविंद्र देवांगन, शिवेंद्र परिहार सहित संबंधित अधिकारी प्रभारी कार्यपालन अभियंता प्रकाश चंद थावनी, सहायक अभियंता गिरीश दिवान, विनोद मांझी, जल कार्य निरीक्षक नारायण सिंह ठाकुर के साथ बैठक ली गई।

नलों में टोंटी, पाइप लाइन का विस्तार बनी प्राथमिकता

बैठक में वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की समस्या, अनावश्यक जल बहाव एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई। महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वार्ड क्षेत्र में जहां-जहां अनावश्यक रूप से पानी बह रहा है, वहां सार्वजनिक नलों में टोटी लगवाकर पानी की बर्बादी को तत्काल रोका जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पानी की समस्या को प्राथमिकता के साथ लेते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।

महापौर ने आगे कहा कि शहर के ऐसे क्षेत्र जहां अब तक पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई है, वहां जल्द से जल्द पाइपलाइन विस्तार की कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि नलों से टुल्लू पंप लगाकर अवैध रूप से पानी खींचने वालों के खिलाफसख्त कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे मामलों में पंप जप्त करने के साथ संबंधित नल कनेक्शन को काटा जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल प्रबंधन को लेकर पूरी गंभीरता और जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा वार्ड में किसी भी प्रकार की पानी की समस्या लंबित न रहे। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे पानी की बर्बादी न करें और जल संरक्षण में सहयोग प्रदान करें, ताकि सभी को समान रूप से जल उपलब्ध हो सके।

महापौर ने कहा कि गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है, इसे ध्यान में रखते हुए शहर के सभी वार्डों में नागरिकों को किसी भी प्रकार की जल समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास खबर

रायपुर में 23 मार्च को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, 100 से अधिक पदों पर होगी भर्ती

रायपुर । जिले के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा 23 मार्च 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैम्प में निजी क्षेत्र के दो नियोजक शामिल होंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड रायपुर द्वारा अर्बन प्रमोटर (महिला/पुरुष) के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं एवं स्नातक/स्नातकोत्तर निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा।इसके अतिरिक्त पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन के 05 पदों पर भी भर्ती की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास निर्धारित है। इन पदों के लिए 10,000 रुपये से 14,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा, आधार कार्ड तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय, रायपुर से संपर्क कर सकते हैं।

सड़क सुरक्षा की दिशा में जिले में हेलमेट बैंक की अभिनव पहल

कोंडागांव। बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह ने शुक्रवार को कोंडागांव विकासखंड के ग्राम मसोरा में संचालित 'हेलमेट बैंक' का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में यह एक सराहनीय पहल बताते हुए अन्य स्थानों में भी हेलमेट बैंक का विस्तार करने के निर्देश दिए। इस अभियान के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के पास हेलमेट नहीं होता, वे यहाँ से स्वैच्छिक रूप से 10 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से हेलमेट लेकर यात्रा कर सकते हैं और उपयोग के बाद उसे पुन: पंचायत में जमा कर देते हैं, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। यह पहल ग्रामीणों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा हेलमेट के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जिले में मसोरा के अलावा ग्राम बनियागांव, मर्दापाल, मांझी आठगांव, लंजोड़ा, अनंतपुर, मस्सूकोकड़ा, माकड़ी और बड़े राजपुर में हेलमेट बैंक की शुरुआत की गई है।

ईएमआरएस सुकमा में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, 25 मार्च को वॉक-इन इंटरव्यू

सुकमा । एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह साक्षात्कार 25 मार्च 2026 को प्रात: 9 बजे से विद्यालय परिसर में होगा। भर्ती के तहत PGT (रसायन शास्त्र), PGT (अर्थशास्त्र) एवं TGT (सामाजिक विज्ञान) के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों की योग्यता नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के मानदंडों के अनुसार निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज एवं स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। पूर्व में जारी विज्ञप्ति में त्रुटिवश यह नियुक्ति संविदा लिखा गया है वास्तव में यह नियुक्ति अतिथि शिक्षक के रूप में की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में जल क्रांति का नया अध्यायः जल जीवन मिशन 2.0 पर ऐतिहासिक एमओयू

श्रीकंचनपथ समाचार

ग्रामीण जल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम - मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ विधानसभा में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केन्द्र और राज्य के बीच एमओयू कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल की वर्चुअल मौजूदगी में अधिकारियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर एक्सचेंज किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में यह पहल ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि हर घर जल के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हुये एमओयू से इन कार्यों में गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के विस्तारित चरण, जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। इस चरण में जल सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ जनभागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 41 लाख 30 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों, यानी लगभग 82.66 प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। श्री साय ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत दूरस्थ, वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों तक शुद्ध पेयजल पहुंचने से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पहले पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि मिशन 2.0 के तहत ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही जल संवर्धन, पुनर्भरण तथा योजनाओं के संचालन और रखरखाव को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि इस एमओयू के माध्यम से पारदर्शी और तकनीक आधारित जल सेवा प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण और अधिक व्यवस्थित एवं सुदृढ़ होगा।

मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री से 1300 करोड़ रुपये की विशेष स्वीकृति का आग्रह भी किया। इस स्वीकृति से 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के 3 हजार से अधिक गांवों तक पेयजल पहुंचाने में मदद मिलेगी। अंत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से छत्तीसगढ़ न केवल हर घर जल का लक्ष्य हासिल करेगा, बल्कि सतत जल प्रबंधन और ग्रामीण जल शासन में भी नए मानक स्थापित करेगा। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल ने कहा कि आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस एमओयू के बाद छत्तीसगढ़ में पाइप लाइन एवं संरचनाओं के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी की पहुँच सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को इसके तहत सशक्त अधिकार प्राप्त होंगे और इन संरचनाओं के रख रखाव के लिए वे जिम्मेदार होंगे। श्री पाटिल ने कहा कि जिला प्रशासन के जरिये पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी एवं आवश्यकता होने पर सहायता भी करेंगे। उन्होंने बताया कि आज का यह एमओयू जल शक्ति मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन का साझा प्रयास का परिणाम है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर स्वच्छ एवं निर्बाध पानी की पहुँच का सपना साकार होगा।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश टोप्पो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

चैत्र नवरात्रि पर्व पर गन्ना किसानों को मिली बड़ी सौगात

उप मुख्यमंत्री शर्मा के विशेष प्रयासों से भोरमदेव शक्कर कारखाने ने जारी किए 5.97 करोड़

श्रीकंचनपथ समाचार

कवर्धा। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर गन्ना किसानों को बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, राम्हेपुर (कवर्धा) द्वारा गन्ना किसानों को 5.97 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही कारखाना द्वारा अब तक गन्ना किसानों को 57.48 करोड़ का भुगतान पूर्ण किया जा चुका है। नियमित और समयबद्ध भुगतान से क्षेत्र के किसानों में उत्साह, संतोष और प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है।

कलेक्टर एवं कारखाने के प्राधिकृत अधिकारी गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया निरंतर जारी है, जिससे सहकारी व्यवस्था में किसानों का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। कारखाना प्रबंधन ने बताया कि यह निरंतरता किसानों की आर्थिक मजबूती के साथ-साथ कारखाने के सुचारु संचालन को भी स्थायित्व प्रदान कर रही है। कारखाना प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चालू पेराई सत्र में 255818 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई तथा 3,09,120 क्विंटल शक्कर का उत्पादन किया जा चुका है। यह उपलब्धि किसानों के सहयोग, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और कारखाने की बेहतर कार्यक्षमता का संयुक्त परिणाम मानी जा रही है।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना क्षेत्र के किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति का मजबूत आधार बना हुआ है। कारखाने द्वारा स्वच्छ के अतिरिक्त रिकवरी राशि का भुगतान, शासन द्वारा प्रदत्त बोनस, रियायती दर पर शक्कर वितरण, उन्नत बीज उपलब्ध कराना, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कारखाना परिसर में किसानों के लिए सर्वसुविधायुक्त बलराम सदन, तथा मात्र 5 में गरम भोजन की कैंटीन सुविधा सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कारखाने के द्वारा स्थापना के समय से आज तक किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है तथा प्रारंभ से ही जिले की अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में कार्य किया जा रहा है। गन्ने की फसल के लिए किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य की गारंटी प्रदान करना, जिससे उनका आर्थिक हित सुरक्षित बना रहे। प्रदेश में फसल विविधता को बनाए रखने तथा शासन की नीति अनुसार धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका। क्षेत्र के लोगों के लिए स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना। गन्ना फसल के लिए संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित करना, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र, परिवहन एवं कटाई आदि से जुड़े हजारों लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन। प्रदेश की पीडीएस व्यवस्था के अंतर्गत शक्कर वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को बाजार मूल्य से कम दर पर शक्कर उपलब्ध कराना, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान। जिला कबीरधाम के स्थानीय बाजार को वित्तीय तरलता प्रदान कर उसके विकास में योगदान देना।

कलेक्टर के मार्गदर्शन में अग्नि सुरक्षा कार्यशाला

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में भीषण गर्मी के पूर्व अग्नि सुरक्षा के मद्देनजर आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में कपड़ा व्यापारी एवं दवा व्यापारी सहित जिला प्रशासन की टीम ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य गर्मी के समय होने वाले संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस दौरान नगर सेना के निर्देशक चंद्रमोहन सिंह ने व्यापारियों को आग लगने के प्रमुख कारणों, उससे बचाव के उपायों एवं आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही अग्निशमन उपकरणों के उपयोग का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया।

सिंह ने उपस्थित व्यापारियों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करें तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचित करें। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों ने इस पहल को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें आग से बचाव और सुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। सभी व्यापारियों ने कहा कि हम सभी शासन एवं प्रशासन के साथ है । इस अवसर पर अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर, एसडीएम रायपुर नंदकुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ग्राम जामगांव में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का हुआ आयोजन

श्रीकंचनपथ समाचार

कोंडागांव। राज्य शासन के निर्देशानुसार जनसमस्याओं के समाधान हेतु जिले के विभिन्न गांवों में लगातार जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत फरसगांव अंतर्गत जिले के दुरस्थ अंचल के ग्राम जामगांव में गुरूवार को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया और ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई, जनपद अध्यक्ष मानकू राम नेताम जनपद उपाध्यक्ष जददूराम नाग, जिला पंचायत सदस्य जयलाल नाग, सरपंच संघ के अध्यक्ष झाड़ी राम सलाम, सरपंच अरूण नेताम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और अश्वन कुमार पुसाम, जनपद पंचायत फरसगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेन्द्र नेताम उपस्थित रहे। शिविर में ग्रामवासियों को विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई। साथ ही ग्रामीणों को सायबर सुरक्षा के संबंध में भी जागरूक किया गया। जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामवासियों से कुल 179 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में मत्स्य विभाग द्वारा 02 मछली जाल वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। राजस्व विभाग द्वारा 59 डिजिटल किसान किताब का वितरण, शिक्षा विभाग द्वारा 15 जाति प्रमाण पत्र वितरण, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को 02 बैसाखी, 04 व्हीलचेयर और 02 श्रवण यंत्र प्रदाय किया गया। आत्मनिर्भरता दलहन मिशन के तहत 20 किसानों को उड़द बीज वितरण किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 06 जॉब कार्ड और श्रम विभाग से 14 श्रम कार्ड वितरण किया गया। शिविर में विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत सामग्री प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने खुशी जताते हुए शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

शहीदी दिवस पर गूंजेगा संकल्पः 'माय भारत, मेरी जिम्मेदारी' के साथ छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में युवा करेंगे राष्ट्र निर्माण का आगाज

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत 'माय भारत' प्लेटफॉर्म द्वारा इस वर्ष शहीदी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। 23 मार्च 1931 को महान क्रांतिकारी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने मातृभूमि की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए थे।

उन्हीं अमर बलिदानियों की स्मृति और सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना के साथ-साथ नागरिक कर्तव्यों के प्रति गहरी जागरूकता पैदा करना है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें।

इस वर्ष के आयोजनों की मुख्य विशेषता माय भारत, मेरी जिम्मेदारी थीम है, जिसके तहत 23 मार्च को पूरे प्रदेश में एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में युवा शामिल होकर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेंगे। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला 19 मार्च से ही डिजिटल क्विज और रील मेकिंग जैसी नवाचारपूर्ण प्रतियोगिताओं के साथ शुरू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, 22 मार्च को 'माय भारत सिविक सेंस चैलेंज' के अंतर्गत स्वच्छता, सड़क सुरक्षा और श्रमदान आधारित जन-जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जो युवाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व का पाठ सिखाएंगी।माय भारत के राज्य निदेशक, अर्पित तिवारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान केवल स्मरण का विषय नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए अपने कर्तव्यों को समझने की एक बड़ी प्रेरणा है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अभियान के माध्यम से शहीदी दिवस को एक जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है, जहां युवा केवल दर्शक की भूमिका में न रहकर 'परिवर्तन के वाहक' बनेंगे। इन आयोजनों के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में एकता, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिकता का एक सशक्त संदेश प्रसारित किया जाएगा, जो एक समृद्ध और विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा।

भीषण गर्मी व लू से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेश में भीषण गर्मी और ताप की लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए निदेशक, ट्रेनिंग ऑपरेशन अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा बचाव हेतु उपाय के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देशानुसार भीषण गर्मी व ताप की लहर से बचने के संबंध में गर्मी के पहले एवं गर्मी के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

साथ ही गर्मी शुरू होने से पहले ही नागरिकों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने, पर्याप्त पानी पीने की आदत डालने तथा स्थानीय मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं एवं बीमार व्यक्तियों का ध्यान रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गर्मी से संबंधित बीमारियों के लक्षणों और प्राथमिक उपचार की जानकारी रखना भी आवश्यक बताया गया है। गर्मी के दौरान दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। प्यास न लगने पर भी नियमित अंतराल में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने और बाहर निकलते समय सिर को ढकने के लिए टोपी, गमछा या छाते का उपयोग करने को कहा गया है। अधिक तापमान के समय भारी और अधिक ऊर्जा वाली गतिविधियों से बचने, यात्रा के दौरान पानी साथ रखने तथा शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड पेयों से परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिक प्रोटीन युक्त एवं बासी भोजन से बचें तथा हल्का और ताजा भोजन करें। घर से बाहर कार्य करने वाले लोग अपने सिर, गर्दन और चेहरे को ढककर रखें तथा गीले कपड़ों का उपयोग करें। बच्चों और पालतू जानवरों को खड़ी गाड़ियों में अकेला न छोड़ने तथा पशुओं को छाया में रखने और उन्हें पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है।

इसके अलावा घर को ठंडा बनाए रखने के लिए पर्दे, शटर या सनशेड का उपयोग करने और रात में खिड़कियां खोलकर वेंटिलेशन बनाए रखने की सलाह दी गई है। शरीर को ठंडा रखने के लिए बार-बार ठंडे पानी से स्नान करने तथा गीले कपड़ों का उपयोग करने को कहा गया है। ओआरएस, नींबू पानी, छाछ, लस्सी जैसे पेय पदार्थों का सेवन कर शरीर को हाइड्रेट रखने की सलाह दी गई है।

विशेष परिस्थितियों में चिकित्सक से परामर्श लेने की भी बात कही गई है।हीट स्ट्रोक की स्थिति में व्यक्ति को तुरंत ठंडी या छायादार जगह पर लिटाने, उसके शरीर को गीले कपड़े से पोंछने या ठंडे पानी का छिड़काव करने तथा ओआरएस या नमक-चीनी घोल पिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने-पीने के लिए न दें और शीघ्र ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। एक घंटे के भीतर सुधार न होने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेने की सख्त हिदायत दी गई है।

खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026: तैयारियों को लेकर संभागायुक्त महादेव कांवरे ने ली बैठक

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। संभागायुक्त महादेव कांवरे की अध्यक्षता में कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर में स्थित सभाकक्ष में खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा आयोजन की जानकारी एवं रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उल्लेखनीय है कि यह प्रतियोगिता 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगी, जिसमें लगभग 3800 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। संभागायुक्त ने अन्य अधिकारियों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्वीमिंग पूल, कोटा स्टेडियम में जाकर आयोजन की तैयारियों का जायज़ा लिया।

बैठक में संभागायुक्त कांवरे ने प्रतिभागियों एवं उनके साथ आने वाले सहयोगी स्टाफकी सुविधा के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर स्टॉल स्थापित कर ड्यूटी लगाई जाए, ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने पर्याप्त संख्या में वॉलन्टियर्स की नियुक्ति करने तथा उन्हें आयोजन में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों जैसे 'बेस्ट वॉलन्टियर' को मेडल, वॉलन्टियर सर्टिफिकेट एवं आयोजन के प्रचार-प्रसार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आयोजन स्थलों पर स्वच्छता, स्वच्छताकर्मियों की ड्यूटी, पेयजल व्यवस्था तथा वेस्ट मैनेजमेंट की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने सभी वेन्यू स्थल एवं खिलाड़ियों के ठहरने के स्थान पर मेडिकल टीम तैनात करने तथा खेल स्थलों एवं अन्य राज्यों से आये दलों के आवास स्थलों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा आवश्यकतानुसार डी.जी.सेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने जिला खेल अधिकारी को उद्घाटन व समापन समारोह स्थल की जानकारी आगामी बैठक में उपलब्ध कराने एवं प्रतिभागियों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने कहा। वाहनों में चस्पा करने एवं डायरेक्टरी बनाने करने के निर्देश दिए।

नेपो किड के ठप्पे को मिटाने के लिए क्या आलिया ने उठाया ये कदम?

अपने प्रोडक्शन की फिल्म को लेकर कही बड़ी बात

आलिया भट्ट हाल ही में प्रोड्यूसर बनी हैं। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म से जुड़े इवेंट में आउटसाइडर्स के लिए बड़ी बात कही।

आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने नए प्रोडक्शन प्रोजेक्ट 'डोंट बी शाय' को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह इस फिल्म के जरिए इंडस्ट्री के 'आउटसाइडर्स' यानी नए चेहरों को मौका देने जा रही हैं।

आउटसाइडर्स को मौका देंगी आलिया

यह बात आलिया ने करण जोहर के साथ अमेजन प्राइम के इवेंट के दौरान शेयर की, जहां दोनों के बीच मजेदार बातचीत भी देखने को मिली। करण ने मजाक करते हुए कहा कि आलिया अब एक समझदार प्रोड्यूसर बन चुकी हैं, वहीं आलिया ने जवाब दिया कि उन्होंने 'बेस्ट से सीखा है' कि नए एक्टर्स को कैसे लॉन्च किया जाता है। जब करण ने उनसे पूछा कि क्या फिल्म में आउटसाइडर्स होंगे, तो आलिया ने हां में जवाब दिया। इस पर करण ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें उन पर बहुत गर्व है।

क्या है फिल्म की कहानी?

'डोंट बी शाय' एक आने वाली फिल्म है, जो एक 20 साल की लड़की की कहानी पर आधारित है, जिसकी परफेक्ट लाइफ अचानक बदल जाती है। इस फिल्म को आलिया अपनी बहन शाहीन भट्ट के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रही हैं। कुल मिलाकर, आलिया अब सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि नए टैलेंट को आगे लाने वाली प्रोड्यूसर के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं।

लैक्मे फैशन वीक में माहिका शर्मा बनीं शोस्टॉपर, अनामिका खन्ना के 'इम्परफेक्ट फ्लावर्स' कलेक्शन ने लूटी महफिल

मुंबई में लेकमे फैशन वीक के पहले दिन मॉडल माहिका शर्मा ने अपना जलवा बिखेरा। उन्होंने डिजाइनर अनामिका खन्ना के लिए शोस्टॉपर बनकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

माहिका शर्मा ने रैंप पर व्हाइट फ्लोई ड्रेप आउटफिट में बेहद ग्रेसफुल एंट्री ली। उनके लुक को खास बनाने के लिए उन्होंने फ्रिल्स वाला कस्टमाइज्ड हैंडबैग कैरी किया, साथ में फ्रिल्ड फुटवियर और ड्रॉप ईयररिंग्स पहने। बालों को उन्होंने साफ-सुथरे बन में बांधा था, जिसमें सामने की ओर कुछ लटें खुली रखी थीं।

'इम्परफेक्ट फ्लावर्स' से इंस्पायर्ड था आउटफिट

मीडिया से बात करते हुए महिएका ने बताया कि यह दूसरी बार है जब वह अनामिका खन्ना के लिए रैंप वॉक कर रही हैं, लेकिन इस बार वह उनके लिए एक्सक्लूसिव थीं।

वहीं, अनामिका खन्ना ने अपने कलेक्शन के बारे में बताते हुए कहा कि यह 'इम्परफेक्ट फ्लावर्स' से इंस्पायर्ड है। उनका कहना था कि जैसे गुलाब वहां भी उगता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, उसी सोच को उन्होंने अपने डिजाइन में दिखाया है।

इंडियन टीम को दी बधाई

माहिका ने इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम की टी20 वर्ल्ड कप में जीत पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी टीम पर गर्व है, लेकिन उनके लिए 'प्लेयर ऑफद टीम' हार्दिक पंड्या हैं।

अनामिका खन्ना के एके7ओके लेबल के इस कलेक्शन में मल्टीपर्पज आउटफिट्स देखने को मिले, जिन्हें अलग-अलग तरीकों से स्टाइल किया जा सकता है। इसमें धोती पैंट्स, रफल्ड टॉप्स, को-ऑर्ड सेट्स और फ्लोर-लेंथ गाउन्स शामिल थे।

साथ ही हैंड एम्ब्रॉयडरी, गोल्ड जरी वर्क, 3डी डिटेलिंग और असिमेट्रिकल डिजाइन ने कलेक्शन को और खास बना दिया। इस शो की एक खास बात यह भी रही कि एके7ओके के जरिए मेन्सवियर को भी पेश किया गया।

मैं अपनी शर्तों पर जीती हूं, सिंगल रहना मेरी पसंद : दिव्या दत्ता

अभिनेत्री दिव्या दत्ता पर्दे पर जितने दमदार तरीके से हर एक किरदार को पेश करती हैं, वास्तविक जिंदगी में भी अपनी बेबाकी और सच्चाई से भरी बातों के लिए जानी जाती हैं। इसी कड़ी में दिव्या समाज की पुरानी और पितृसत्तात्मक सोच पर खुलकर बात करती नजर आईं।

दिव्या ने सिंगल रहने, शादी और मातृत्व को लेकर समाज की अपेक्षाओं पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान की जिंदगी को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता और हर किसी की कहानी अलग-अलग होती है। दिव्या से जब पूछा गया कि आज के समय में सिंगल रहना कितना मुश्किल है और क्या समाज अब भी मानता है कि कोई महिला शादी या बच्चे होने से ही पूरी होती है, तो उन्होंने अपनी राय रखते हुए बताया, चाहे मेरे पास पार्टनर हो या मैं सिंगल हूं, मैं अपनी जिंदगी का मजा लेती हूं और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मुझे लगता है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है। यह आम राय बनाना कि पार्टनर होना अच्छा है या सिंगल रहना अच्छा है, यह किसी के लिए भी सही नहीं। जो आपके लिए सही काम करता है, वही सबसे बढ़िया है। मेरे लिए यह सही है और मैं इससे खुश हूं।

उन्होंने आगे कहा, मेरा स्पष्ट मानना है कि लोगों को दूसरों की जिंदगी के फैसलों पर राय नहीं बनानी चाहिए। अगर किसी को अच्छा पार्टनर मिल गया, तो उनके लिए सही है। अगर नहीं मिला, तो उन्हें जो सही लगे, वही करना चाहिए। आप किसी की जिंदगी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। मेरी जिंदगी ऐसी ही रही है और मैं इसका मजा लेती हूं। इसलिए जो भी फैसले मैंने लिए, उन पर मुझे गर्व है।

समाज में आज भी मौजूद पितृसत्तात्मक सोच पर बात करते हुए दिव्या ने कहा, तरक्की के बावजूद ये पुरानी सोच बनी हुई है। शिक्षा का इससे कोई लेना-देना नहीं, यह बस एक सोच है। हर इंसान का सफर अलग होता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए, न कि तुलना।

सुपर कॉप से सुपरहीरो बनीं अदा शर्मा

भारतीय सिनेमा में सुपरहीरो की छवि आमतौर पर बहादुरी, ईमानदारी और दुनिया को बचाने के जज़्बे से जुड़ी होती है। लेकिन इस बार दर्शकों को सुपरहीरो का एक ऐसा रूप देखने को मिलने वाला है, जो इन तमाम धारणाओं को तोड़ता नजर आएगा। एक्शन और इंटेंस किरदारों से पहचान बना चुकी Adah Sharma अब एक ऐसे अवतार में सामने आने जा रही हैं, जो जितना चौंकाने वाला है उतना ही दिलचस्प भी।

अदा शर्मा का सबसे अनोखा अवतार 'सुपर वेल्ली'

हाल के वर्षों में सनफ्लावर, द केरल स्टोरी, कमांडो और बस्तर द नक्सल स्टोरी जैसी परियोजनाओं में अपने दमदार अभिनय से प्रभावित करने के बाद अदा अब एक ऐसे किरदार में नजर आएंगी जो परंपरागत सुपरहीरो की परिभाषा को ही उलट देता है। उनके आगामी प्रोजेक्ट में वह एक सुपर कॉप के रूप में दिखाई देंगी, लेकिन यह सुपर कॉप किसी आदर्शवादी नायक की तरह नहीं, बल्कि एक आलसी, भ्रष्ट और पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल सुपरहीरो है।

फिल्म में अदा जिस किरदार को निभा रही हैं उसका नाम है वेल्ली — एक ऐसा सुपरहीरो जो नियमों का पालन करने के बजाय उन्हें तोड़ता है, झूठ बोलता है और कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि वह दुनिया को बचाने के बजाय उसे मुश्किल में डाल सकता है। यही अनोखा और डार्क-सटायरिकल कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है और सुपरहीरो जॉनर को एक बिल्कुल नया ट्विस्ट देता है।

हाल ही में जारी हुए फर्स्ट लुक ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है। फैंस अदा के इस अजीब, बेतुके और मजेदार किरदार की झलक देखकर उत्साहित हैं और यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर सुपर वेल्ली किस तरह की दुनिया में दर्शकों को लेकर जाने वाला है। अगर फर्स्ट लुक के संकेतों पर भरोसा किया जाए, तो यह किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे अनोखे सुपरहीरो में से एक साबित हो सकता है।

दिलचस्प बात यह भी है कि अदा शर्मा ने अपने करियर में हमेशा अलग-अलग तरह के किरदारों को अपनाकर यह साबित किया है कि वह खुद को किसी एक जॉनर तक सीमित नहीं रखना चाहतीं। 1920 से अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने हॉरर, ड्रामा, कॉमेडी और एक्शन—हर शैली में अपनी पहचान बनाई है। अब सुपर वेल्ली के साथ वह अपनी फिल्मोग्राफी में एक और ऐसा अध्याय जोड़ने जा रही हैं, जो न सिर्फ दर्शकों को चौंकाएगा बल्कि भारतीय सुपरहीरो कहानियों के अंदाज़ को भी नया रंग दे सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो जल्द ही दर्शकों को बड़े पर्दे पर एक ऐसा सुपरहीरो देखने को मिलेगा जो परंपरा से बिल्कुल अलग, थोड़ा पागल, थोड़ा आलसी और पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है — सुपर वेल्ली

मीठा खाने की इच्छा को कम करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

मीठा खाने की इच्छा एक आम समस्या है, खासकर जब हम तनाव में होते हैं या थकावट महसूस करते हैं। यह इच्छा न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, बल्कि हमारे वजन को भी बढ़ा सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप मीठा खाने की इच्छा को कम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी जीवनशैली में बदलाव ला सकते हैं।

पानी पीएं

जब भी आपको मीठा खाने की इच्छा हो, सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं। कई बार हमें लगता है कि हम भूखे हैं, जबकि वास्तव में हमें प्यास लगी होती है। पानी पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है और मीठे की इच्छा कम हो जाती है। इसके अलावा पानी पीने से हमारे शरीर में तरलता बनी रहती है और पाचन क्रिया भी सही तरीके से काम करती है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है।

फल खाएं

फल प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं और इनमें विटामिन्स, खनिज और फाइबर होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जब भी आपको मीठा खाने की इच्छा हो, एक केला या सेब खा लें। इससे आपकी मीठे की इच्छा भी पूरी होगी और शरीर को जरूरी पोषण भी मिलेगा। फल खाने से आपको ताजगी का एहसास होगा और यह एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प भी है। इसके अलावा फल खाने से आपको ऊर्जा भी मिलेगी।

डार्क चॉकलेट खाएं

अगर आपको चॉकलेट खाने का बहुत शौक है तो डार्क चॉकलेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें कम चीनी होती है और यह शरीर के लिए फायदेमंद तत्वों से भरपूर होती है। डार्क चॉकलेट खाने से हमारी मीठे की इच्छा भी शांत होती है और साथ ही यह हमें ऊर्जा भी देती है। इसके अलावा इसमें मौजूद तत्व हमारी सेहत के लिए लाभकारी होते हैं, जिससे हम स्वस्थ और ताजगी महसूस करते हैं।

योग और ध्यान करें

योग और ध्यान हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब भी आपको मीठा खाने की इच्छा हो, थोड़ी देर योग या ध्यान करें। इससे आपका मन शांत होगा और मीठे की इच्छा कम होगी। योग और ध्यान से न केवल मानसिक तनाव कम होता है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह एक प्रभावी तरीका है, जिससे आप मीठे की आदत को नियंत्रित कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

प्रोटीन युक्त खाना खाएं

प्रोटीन युक्त खाना खाने से हमारी भूख कम होती है और हमें लंबे समय तक संतुष्टि मिलती रहती है। जब भी आपको मीठा खाने की इच्छा हो, थोड़ी मात्रा में मूंगफली या बादाम खा लें। इससे आपकी मीठे की इच्छा भी शांत होगी और साथ ही आपको जरूरी पोषण भी मिलेगा। इसके अलावा प्रोटीन युक्त खाने से ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है और आप अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। यह एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है।

खास खबर

सरगुजा ओलंपिक में जिले के 303 खिलाड़ी संभाग स्तर पर दिखाएंगे दम

कोरिया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सरगुजा ओलंपिक 2025-26 के अंतर्गत संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह प्रतियोगिता 21 मार्च से 23 मार्च 2026 तक सरगुजा संभाग मुख्यालय, अंबिकापुर में आयोजित होगी। जिले में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन संभाग स्तर के लिए किया गया है। चयनित खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में कोरिया जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोरिया जिले से कुल 303 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 154 पुरुष एवं 149 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों की व्यवस्था और संचालन के लिए 33 सदस्यीय स्टाफ दल भी नियुक्त किया गया है, जिसमें 21 पुरुष एवं 12 महिलाएं शामिल हैं। अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खिलाड़ियों से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने की अपेक्षा जताई।

हर घर नल से जल ने बदली जिंदगीः फुलझर की अनीता सिंह बनीं बदलाव की मिसाल

एमसीबी। जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत फुलझर में जल जीवन मिशन ने ग्रामीण जीवन की तस्वीर ही बदल दी है। कभी स्वच्छ पेयजल के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करने को मजबूर रहने वाले ग्रामीण अब अपने घरों में ही शुद्ध पानी की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस बदलाव की जीती-जागती मिसाल हैं फुलझर की अनीता सिंह, जिनकी जिंदगी इस योजना से पूरी तरह बदल गई है। अनीता सिंह बताती हैं कि पहले उन्हें कुएं और हैंडपंप से पानी लाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, जिसमें समय और मेहनत दोनों ही अधिक लगते थे। कई बार पानी की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं होती थी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती थीं।

छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिन बारिश की संभावना, आंध्रप्रदेश के साइक्लोन का असर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में द्रोणिका और साइक्लोन के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी के अनुसार 16 मार्च को उत्तर छत्तीसगढ़ में बनी द्रोणिका का असर अब समाप्त हो चुका है। वहीं, एक नई द्रोणिका झारखंड के ऊपर सक्रिय है, जिसका असर उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा.इसके अलावा आंध्र तट पर एक साइक्लोन बना हुआ है। जिसका प्रभाव दक्षिण छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर संभाग में पड़ेगा. यहां अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं, मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ विधानसभा बजट सत्र
मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों और अधिकारियों को दिया धन्यवाद

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के सफल समापन पर मंत्रीगण एवं विधायकगण ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया और सफल सत्र के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी के समन्वय और सहयोग से ही यह सत्र सार्थक और सफल बन पाया है।

लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के साथ अनेक महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना ही इसका मूल दायित्व है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस बजट सत्र के दौरान लगभग 585 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन किया जो एक अत्यंत प्रेरणादायक पहल है। इससे यह संदेश गया है कि राज्य सरकार भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है, जिसका सीधा संबंध राज्य की आंतरिक सुरक्षा, शांति और समृद्धि से है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट सत्र में कुल 15 बैठकें आयोजित हुईं और यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण एवं परिणामकारी रहा। सत्र के दौरान माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन द्वारा कृतज्ञता व्यक्त की गई तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी सम्पन्न हुए।

उन्होंने कहा कि इस सत्र में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026, छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक-2026 तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक-2026 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने संबंधी विधेयक तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित हुए, जो युवाओं के भविष्य और पारदर्शी भर्ती प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सत्र के दौरान सदन के सदस्यों ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, प्रश्न पूछे और अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया, जो लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है।

उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे भले ही अस्वस्थता के कारण सदन में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने लगातार डिजिटल माध्यम से सदन की कार्यवाही पर नजर रखी।मुख्यमंत्री ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सत्र के सफल संचालन के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सभी विधायकगण, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा, सुरक्षा कर्मियों एवं समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आप सभी ने सदन की महत्वपूर्ण कार्यवाही और जनहित के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अंत में मुख्यमंत्री साय ने चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

एलपीजी, पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता शासन ने जारी किए सख्त निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

कोरिया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा 13 मार्च 2026 को हुई समीक्षा के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता और वितरण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ऑयल कंपनियों के पास तीनों ईंधनों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से एलपीजी की बार-बार बुकिंग या पेट्रोल-डीजल का संग्रहण करने से बचने की अपील की गई है।

खाद्य विभाग द्वारा एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल के स्टॉक की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलेवार स्टॉक, वितरण और शेष मात्रा की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध भंडारण और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नियमित जांच और छापेमारी की जा रही है। किसी भी अनियमितता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-233-3663, 1967 या राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 0771- 2511975 व कोरिया जिला में कंट्रोल कक्ष स्थापित किया गया है जहाँ 7648093823 पर संपर्क कर सकते हैं। सभी शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित अंतराल के अनुसार ही रिफिल बुकिंग कराएं। नगरीय क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल निर्धारित है। अफवाहों के कारण बार-बार बुकिंग करने से बचने की अपील की गई है। व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति वर्तमान में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थानों को दी जा रही है। साथ ही, बिना लाइसेंस 100 किलोग्राम से अधिक एलपीजी भंडारण पर प्रतिबंध है।

होटल एवं अन्य प्रतिष्ठानों को गैस की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग और सीमित मेन्यू अपनाने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी या व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी गैस एजेंसियों और उचित मूल्य दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एलपीजी बुकिंग, वितरण और सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके।

पर्यटन और रोजगार को मिला बढ़ावा
मगरमच्छ संरक्षण से बदली कोटमीसोनार की तस्वीर

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मगरमच्छों के संरक्षण और पुनर्वास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी और मगरमच्छ के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ के जांजगीर-चांपा वनमण्डल के अंतर्गत स्थापित मगरमच्छ संरक्षण आरक्षिती केन्द्र, कोटमीसोनार आज वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण विकास और पर्यटन का सफल उदाहरण बनकर उभर रहा है। इस केन्द्र का निर्माण मगरमच्छों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से किया गया है।

मगरमच्छ की सभी प्रजातियाँ लुप्तप्राय नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों की आबादी बहुत कम हो जाने के कारण, उनके प्रबंधन और सुरक्षात्मक कानूनों की आवश्यकता है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना भारत में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना, कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से मगरमच्छों की संख्या को बढ़ावा देना और प्राकृतिक वातावरण में नवजात शिशु के जीवित रहने की कम दर का समाधान करना है।

वन विभाग द्वारा मगरमच्छ संरक्षण के लिए जांजगीर-चांपा जिला के ग्राम कोटमीसोनार स्थित मुड़ातालाब को चिन्हित कर जिले के विभिन्न तालाबों से मगरमच्छों को यहां लाकर सुरक्षित वातावरण में छोड़ा गया। वर्तमान में यहां लगभग 250 मगरमच्छ संरक्षित हैं। इस परियोजना की शुरुआत 9 मई 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा शिलान्यास के साथ हुई, जबकि 23 अगस्त 2008 को तत्कालीन वन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। करीब 57.037 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस केन्द्र में 34 हेक्टेयर कोर जोन और 23.037 हेक्टेयर

बफर जोन निर्धारित किया गया है। वन विभाग ने इसे पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया है, जहां पर्यटकों के लिए पैगोडा, वॉच टावर, इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया, चिल्ड्रन पार्क, ऊर्जा पार्क और 3-डी मिनी थिएटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

उल्लेखनीय है कि 1 नवम्बर 2015 से यहां पर्यटन शुल्क लागू किया गया है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण कोटमीसोनार गांव अब एक छोटे बाजार के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को नियमित रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मगरमच्छ संरक्षण आरक्षिती केन्द्र, कोटमीसोनार न केवल वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि पर्यटन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रहा है। कोटमीसोनार स्थित मुड़ातालाब मगरमच्छ संरक्षण-पर्यटन केन्द्र तक पहुंच भी सुगम है। यह जांजगीर जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर तथा बिलासपुर से जयरामनगर होते हुए करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन जांजगीर-नैला (30 किमी), कोटमीसोनार (1 किमी), अकलतरा (9 किमी) और बिलासपुर (30 किमी) हैं।

संभागायुक्त ने लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के दिए सख्त निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

कवर्धा। दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर गोपाल वर्मा उपस्थित रहे। संभाग आयुक्त ने समय सीमा से अधिक लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी मामलों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।

उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए तय समय सीमा के भीतर पूरा करना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करें, ताकि लोगों को भटकना ना पड़ें। आम जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। संभाग आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यों की नियमित समीक्षा करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों का त्वरित व प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

संभाग आयुक्त राठौर ने त्रुटि-सुधार प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि त्रुटि सुधार शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए इस कार्य में विशेष सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि कई प्रकरण अपील स्तर तक पहुंच रहे हैं, अतः सभी मामलों में नियमानुसार सुनवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण में संबंधित पक्षकारों को अनिवार्य रूप से नोटिस जारी किए जाएं, ताकि समयबद्ध सुनवाई एवं निराकरण संभव हो सके और आम जनता को अनावश्यक भटकना न पड़े। पट्टा संबंधी मामलों पर उन्होंने कहा कि इस विषय में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिनकी गंभीरता से जांच आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर समस्याओं का समाधान किया जाए। संभाग आयुक्त ने सीमांकन एवं नक्शा बटांकन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस दिशा में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में अक्सर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका समय पर निराकरण करना राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी है। विशेष रूप से एसडीएम को इन प्रकरणों पर गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए गए, ताकि आम जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। संभाग आयुक्त राठौर ने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि सप्ताह में निर्धारित दो से तीन दिन नियमित रूप से राजस्व न्यायालय का आयोजन करें। उन्होंने कहा कि कोर्ट की तिथियों की जानकारी आम जनता को पहले से उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक भटकना न पड़े और उन्हें समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन एवं त्रुटि-सुधार के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो तथा इन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राथमिकता से निराकृत किया जाए। साथ ही, विवादित प्रकरणों के संबंध में पूर्व निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और इनके निराकरण में गंभीरता एवं पारदर्शिता बरती जाए। बैठक के दौरान संभाग आयुक्त ने तहसीलवार अविवादित एवं विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि-सुधार, डायवर्सन, अभिलेख शुद्धता एवं नक्शा बटांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर विनय पोयाम, अनुविभागीय अधिकारी संदीप ठाकुर, सागर सिंह, चेतन साहू, शिल्पा देवांगन, डिप्टी कलेक्टर आर.बी. देवांगन, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार बैठक में उपस्थित रहे।

सिन्धी समाज ने निकाली भव्य दुपहिया वाहन रैली, आयो लाल झूलेलाल की रही गूंज शहर में

श्रीकंचनपथ समाचार

जगदलपुर। सिन्धी समाज के ईष्टदेव साईं श्री झूलेलाल जी के जन्मोत्सव पर हर्ष व उत्साह से चेटीचंड मनाया । चैत्र मास को सिन्धी में चेटी कहा जाता है और चांद को चंड इसलिए चेटीचंड का अर्थ हुआ चैत्र का चांद। ये दिन जल के देवता साईं झूलेलाल को समर्पित है।

पूज्य सिन्धी पंचायत अध्यक्ष मनीष मूलचंदानी ने बताया श्री गुरु सँगत गुरुद्वारा कमेटी व सिन्धी पंचायत तत्वाधान में समाज सदस्यों ने साईं झूलेलाल जन्मोत्सव की पूर्व संध्या में 19 मार्च की रात 9 बजे से भजन कीर्तन व भक्ति संगीत संध्या आयोजन किया सिंधु भवन में, धमतरी से आए हितेश जग्यासी, रोशनी जग्यासी द्वारा भजन कीर्तन होने के पश्चात भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। श्री गुरु सँगत गुरुद्वारा कमेटी अध्यक्ष सुंदर भोजवानी ने बताया साईं झूलेलाल अवतरण दिवस एवं सिन्धी नव वर्ष में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुबह 10 बजे से सिन्धी समाज सभी सदस्य, युवा मंडल, सुहिणी सोच महिला विंग सभी सदस्य भगवा रंग के वस्त्र में भव्य दुपहिया वाहन रैली में शामिल रहे।

यह दुपहिया वाहन रैली सिन्धी गुरुद्वारा से निकलकर चाँदनी चौक, शहीद पार्क चौक, कोतवाली चौक, गोल बाजार, सिरहासार चौक, माँ दंतेश्वरी मंदिर, संजय बाजार, चाँदनी चौक होते हुवे रैली सिन्धी गुरुद्वारा पहुंची। पुरे मार्ग में साईं झूलेलाल जी के जयघोष आयो लाल झूलेलाल की पुकार रही। श्री सिन्धी गुरुद्वारा में सुबह 11 बजे से भक्ति संगीत के पश्चात श्री गुरुग्रंथ पाठ साहिब समाप्ति व अरदास, पल्लव, भोग साहिब, प्रसादी वितरण किया गया। गुरुद्वारा कमेटी सचिव ने जानकारी दी सिंधु भवन में दोपहर 2 बजे से आम लंगर किया गया।

खास खबर

महुआ बीनने के विवाद में भाई की हत्या, उम्रकैद

रायगढ़। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने महुआ बीनने के विवाद में सगे भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी खेमराज यादव को उसके छोटे भाई पीतांबर यादव की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही, मृतक की पत्नी को 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की अनुशंसा की। अपर लोक अभियोजक राजेशसिंह ठाकुर के अनुसार, मामला थाना धर्मजयगढ़ के ग्राम रामपुर का है। सगे भाई खेमराज और पीतांबर के बीच जमीन बंटवारे के बाद महुआ पेड़ के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। थाने में पीतांबर के पुत्र मनोज यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन कुधरी डॉड़ में महुआ झाड़ पर वे माता-पिता, छोटी बहन व छोटे भाई के साथ महुआ बीनने गए थे। तभी आरोपी खेमराज आया और 'महुआ मत बीनो, पुराना बदला लूंगा, सबको मार दूंगा' धमकाते हुए पीतांबर के पेट में चाकू मार दिया। गंभीर घायल पीतांबर वहीं गिर पड़े और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने सभी गवाहों के बयान दर्ज कर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खेमराज को दोषी करार दिया। यह फैसला पारिवारिक 22 विवाद के गंभीर परिणामों का उदाहरण है, जो संपत्ति बंटवारे में शांति की आवश्यकता दर्शाता है।

नए बस स्टैंड में चश्मा बेचने वाले पर रंजिश में हॉकी से हमला, अपराध दर्ज

बिलासपुर। तिफरा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक चश्मा विक्रेता पर आधा दर्जन लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। रंजिश में हुए इस विवाद में हमलावरों ने हॉकी का इस्तेमाल किया। घटना मारुति नेक्सा शोरूम के ठीक सामने हुई। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चांटीडीह मेलापारा निवासी गुलाटी पिता लियाकत अली चश्मा बेचने का काम करता है। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 8 बजे वह तिफरा स्थित नेक्सा शोरूम के सामने अपनी दुकान लगाकर चश्मा बेच रहा था। इसी दौरान मजर अली, शेफु अली, मिसम अली, शोहेल अली और उनके अन्य साथी वहां पहुंचे। आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पास रखे हॉकी से गुलाटी पर हमला कर दिया। हमले में पीड़ित के बाएं पैर, बाएं कंधे और कमर के निचले हिस्से में गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद सलीम अली और सलमान अली ने बीच-बचाव कर पीड़ित की जान बचाई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

आनंदम रिजॉर्ट व ढाबों से 28 सिलेंडर जब्त

जांजगीर। जांजगीर-चांपा जिले में घरेलू कुकिंग गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग और भंडारण पर लगाम कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश के बाद विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न होटलों, रिजॉर्ट और ढाबों पर औचक दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और चूल्हे जब्त किए गए हैं। सहायक खाद्य अधिकारी संदीप पांडे और मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने अकलतरा विकासखंड के ग्राम अमरताल स्थित आनंदम रिजॉर्ट के मिस्टर वेज रेस्टोरेंट की जांच की। यहां द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का खुला उल्लंघन पाया गया। टीम ने मौके से 28 व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 1 घरेलू सिलेंडर जब्त किया। तिलई स्थित रोड़ा ढाबा में घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल उपयोग हो रहा था। मौके से 3 घरेलू गैस सिलेंडर, तीन बर्नर वाले 2 चूल्हे, एक बर्नर वाला 1 चूल्हा और रेगुलेटर जब्त किए गए। श्री कृष्णा डेयरी (जांजगीर) कलेक्टोरेट चौक स्थित प्रतिष्ठान में भी नियमों की अनदेखी मिली, जहां से 1 घरेलू गैस सिलेंडर और चूल्हा जब्त किया गया।

बिलासपुर में ऑनलाइन-गेमिंग ऐप का भंडाफोड

रायपुर के होटल से ऑपरेट कर रहा था ऑनलाइन-सट्टा, 2 खाईवाल गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। बिलासपुर में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप का भंडाफोड़ कर फरार खाईवाल राजेश उर्फ राजा बजाज और उसके साथी प्रदीप खत्री को रायपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया है। आरोपी होटल से रिक्की पैनल के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 6.90 लाख रुपए कैश, तीन लग्जरी कार, महंगे मोबाइल, लैपटॉप और बैंक दस्तावेज समेत करीब 45 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। साथ ही 10 से ज्यादा बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेनदेन के दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस ने अब इनकी संपत्ति कुर्क करने का दावा किया है।

पुलिस की एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट (ACCU) और सिविल लाइन पुलिस की टीम लंबे समय से रिक्की पैनल के मास्टरमाइंड और 5 हजार रुपए के इनामी खाईवाल राजा बजाज की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि राजा बजाज फरारी में अपना ठिकाना बदल-बदल कर ऑनलाइन सट्टा ऑपरेट कर रहा है।

पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद पुलिस की टीम रायपुर पहुंची। जहां राजा बजाज होटल के कमरे में ठहरा था। पुलिस ने होटल के रजिस्टर की जांच की, तब पता चला कि रूम महिला के नाम पर बुक है। जहां दबिश देने पर राजा बजाज और प्रदीप खत्री मिले। होटल के कमरे की तलाशी लेने पर कैश, लैपटॉप, मोबाइल और सट्टे का हिसाब-किताब और रजिस्टर बरामद मिला।

देशभर में फैलाए नेटवर्क

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी रिक्की पैनल के जरिए से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। इस पैनल के जरिए कस्टमर को एविएटर, विन्गो, कैसिनो, हॉर्स राइडिंग सहित अन्य ऑनलाइन गेम्स उपलब्ध कराए जाते थे, जिन पर हार-जीत का दांव लगाया जाता था। यह पूरा नेटवर्क पैन इंडिया स्तर पर फैला हुआ था। आरोपी टेलीग्राम के जरिए कस्टमर जोड़ते थे, जबकि व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर उन्हें लिंक उपलब्ध कराया जाता था, जिसके माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेला जाता था।

65% हेड ऑफिस और ब्रांच को 35% का हिस्सा

पूछताछ में पता चला कि, गिरोह के एजेंट ग्राहकों को जोड़ने के बाद हार-जीत का दांव लगाते थे। सट्टे के इस कारोबार में मुनाफे का बंटवारा भी तय

था, जिसमें 65 प्रतिशत हिस्सा हेड ऑफिस और 35 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय ऑपरेटरों को मिलता था।

लगातार ठिकाना बदल-बदल कर खिला रहे थे सट्टा

पुलिस ने सरकंडा के मोपका स्थित गार्डन सिटी निवासी खाईवाल राजेश उर्फ राजा बजाज (34) पिता किशन चंद्र बजाज पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस की टीम भी लगातार उसकी तलाश कर रही थी। इसके साथ ही टीम मंगला के आदित्यनाथ परिसर निवासी प्रदीप खत्री पिता रामचंद खत्री की भी तलाश में थी।

लेकिन, दोनों लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। इस दौरान दोनों घूम-घूमकर ऑनलाइन सट्टा ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस को उनके रायपुर में छिपकर रहने की जानकारी मिली, तब योजना बनाकर रेड कार्रवाई की गई।

पुलिस ने 21 दिसंबर 2025 को तोरवा के हेमूनगर निवासी सटोरिया मनोज पोपटानी पिता नंदलाल पोपटानी को पकड़ला था। उससे पूछताछ में पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ था। उसने पुलिस को बताया था कि वह राजेश बजाज और प्रदीप खत्री के साथ मिलकर सट्टा संचालित करता है। इसी आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी।

गिरफ्तारी के दौरान मुख्य आरोपी राजेश उर्फ राजा बजाज के कब्जे से 6 लाख 90 हजार रुपए बरामद की गई है। इसके अलावा जांच में ऑनलाइन सट्टा के जरिए लाखों रुपए के लेन-देन की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी बिलासपुर और रायपुर में रहकर लगातार ठिकाना बदलते थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा संचालित करते थे।

फर्जी सिम और बैंक खातों से चलता था पूरा खेल

पूरे नेटवर्क को संचालित करने के लिए आरोपी फर्जी सिम कार्ड और फर्जी बैंक खातों का उपयोग करते थे। आम लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते हासिल किए जाते थे और उन्हीं खातों के जरिए सट्टे की रकम का लेन-देन किया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों द्वारा उपयोग किए गए बैंक खातों में लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है।

सटोरियों से कैश और तीन लग्जरी कारें भी जब्त

आरोपियों से पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, कार और रजिस्टर समेत 45 लाख की जब्ती की। जिनमें लैपटॉप, मंहगे मोबाइल, 5 बैंक पासबुक और 5 चेकबुक, होंडा सिटी कार (सीजी 10 एएल 6300), मारुति ब्रेजा कार (सीजी 10 बीएस 2111), मारुति स्विफ्ट डिजायर कार (सीजी 10 ए क्यू 3352), होंडा एक्टिवा, 6 लाख 90 हजार कैश, 2 रजिस्टर (जिनमें ऑनलाइन सट्टा के लाखों रुपए का विस्तृत हिसाब-किताब दर्ज है) शामिल हैं।

एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि, पहली बार किसी सटोरिए के खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। फिलहाल, आरोपी के नाम पर करीब 50 लाख रुपए कीमत का एक मकान मिलने की जानकारी मिली है। अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, जिन्हें जल्द कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि, इस तरह से सट्टे का अवैध कारोबार से लोगों के मेहनत की गाढ़ी कमाई लूटने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस अब आर्थिक प्रहार करने की तैयारी में है। इनकी संपत्ति की जांच के बाद आय-व्यय की जानकारी जुटाकर एंड टू एंड कार्रवाई की जाएगी। ताकि, अवैध कारोबारियों को समूल

आरडीए आवास दिलाने के नाम पर ठगी

ठगों ने 7 लाख लेकर फर्जी अलॉटमेंट लेटर थमाया

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर में रायपुर विकास प्राधिकरण का मकान दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है।

जालसाजों ने एक महिला को फर्जी अलॉटमेंट ऑर्डर (आवंटन पत्र) थमाकर 7.10 लाख रुपये डकार लिए। ठगी का खुलासा तब हुआ जब महिला कब्जा लेने आरडीए कार्यालय पहुंची। अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माना थाना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

जुलाई 2024 में बुना गया ठगी का जाल

माना पुलिस के अनुसार, पीड़िता कविता मंडल (38 वर्ष) निवासी माना कैंप, अपना खुद का घर चाहती थी। इसके लिए उसने जुलाई 2024 में राकेश मंडल, सरिता मंडल और पुनीत सिंह नामक व्यक्तियों से संपर्क किया। इन तीनों ने खुद को आरडीए में अच्छी पैठ होने का दावा किया और कविता को मकान दिलाने का झांसा दिया।

फर्जी दस्तावेज और 7.10 लाख की वसूली

आरोपियों ने 8 जुलाई से 22 जुलाई 2024 के बीच अलग-अलग किस्तों में कविता से कुल 7.10 लाख रुपये वसूले। विश्वास जीतने के लिए उन्होंने कविता को आरडीए के फर्जी सील-सिक्के लगे आवंटन पत्र और अन्य कागजात सौंप दिए। जब कविता इन दस्तावेजों को लेकर आरडीए दफ्तर पहुंची, तो अधिकारियों ने बताया कि ये कागजात पूरी तरह फर्जी हैं और उनके नाम पर कोई मकान आवंटित नहीं हुआ है।

कोर्ट की शरण में पहुंची पीड़िता

धोखाधड़ी का पता चलने पर कविता ने आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे। आरोपी महीनों तक 'आज-कल' और 'अगले महीने' कहकर टालते रहे। अंत में हार मानकर कविता ने कोर्ट में याचिका दायर की। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गुरु प्रसाद देवांगन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए माना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर माना पुलिस ने आरोपी राकेश, सरिता और पुनीत के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरु कर दी है।

37 बकरियां चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, चार मवेशी काटकर बेचे

बिलासपुर। बिलासपुर चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम सेवार में बकरी चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गांव से 37 बकरी और बकरे चोरी किए थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनमें से 4 बकरे कटवाकर कसाई की दुकान में बेच दिए थे। बिक्री से मिले 4 हजार रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार 15 मार्च को ग्राम सेवार के पीड़ितों ने चकरभाठा थाने में सामूहिक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि रात में बाड़े से बड़ी संख्या में बकरियां चोरी हो गई हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने टीम बनाकर जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज में संदिग्धों का हुलिया मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर हेमराज उर्फ हेमू (18) और नजीर खान (20) को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि चोरी की गई बकरियों में से 4 को कटवाकर बेच दिया था। पुलिस ने बिक्री से मिले 4 हजार रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह के अन्य सदस्य अभी फरार हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इनके पकड़े जाने के बाद बाकी बकरियों का पता चलेगा।

गंगोत्री वाटर प्लांट पर छापा हजारों बोतल-पाउच जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। बिलासपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सीपत स्थित गंगोत्री मिनरल वाटर प्लांट पर छापा मारा। इस दौरान भ्रामक लेबलिंग के कारण हजारों पानी की बोतलें और पाउच जब्त किए गए। यह कार्रवाई नवरात्रि और गर्मी के मौसम को देखते हुए जनस्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल और नियंत्रक खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर की गई।

विभाग की तरफसे नवरात्रि और बढ़ती गर्मी के मद्देनजर जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभिहित अधिकारी आर.आर. देवांगन के मार्गदर्शन में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी खीर सागर पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अविषा मरावी और प्रतीक तिवारी की टीम ने यह कार्रवाई की।

पानी बोतलों के लिए गए सैंपल

गंगोत्री मिनरल एंड वाटर प्लांट से पानी की बोतलों के सैंपल भी लिए गए। भ्रामक लेबलिंग के कारण 1 लीटर की 210 पेटियां (प्रत्येक में 12 बोतल), 250 एमएल की 3030 पानी की बोतलें और 250 एमएल के 29,100 पानी के पाउच सीज किए गए।

दो फर्मों को नोटिस जारी

इस दौरान दो अन्य फर्मों को सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए। टीम ने सेवई, साबूदाना, अरहर दाल और चना दाल के नमूने भी एकत्र किए। रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रसाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रसाद कक्ष का भी जायजा लिया गया। मंदिर में भोग प्रमाणन (भोग सर्टिफिकेट) के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। मंदिर परिसर के बाहर लगे ठेलों और गुमटियों की भी जांच की गई। यहां अखाद्य रंग से तैयार चाट को नष्ट कराया गया और संचालकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में जानकारी दी गई।

पुलिस की चौकसी के बाद भी बिक रहा गांजा, 4 जगह से 18 किलो जब्त

भिलाई। जिले में पुलिस के तमाम प्रयास के बाद भी मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ रही है। इसके चलते पुलिस ने बीते 24 घंटे में चार प्रकरणों में 18 किग्रा से ज्यादा गांजा पकड़ी है। आरोपी शहरी और आंचलिक क्षेत्रों में गांजा बिक्री करने जा रहे थे। पुलिस ने धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

बोरी थाना पुलिस ने बताया कि गुरुवार को एक व्यक्ति बाइक (सीजी-07 वीएन 3586) में गांजा छिपाकर बेचने के लिए ग्राम नवागांव की तरफसे जा रहा था। टीम ने डोमा मार्ग डबरी तालाब के पास बाइक चालक को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम ऋषि कुमार सेन पिता नंदकुमार सेन (32वर्ष) निवासी महावीर चौक नवागांव, दुर्ग बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2.80 लाख रुपए का 5.620 किग्रा गांजा मिला। जामुल थाना पुलिस ने ग्राम खेरधा में शीतला तालाब के पास से दिलावर अली नाम के व्यक्ति के कब्जे से 5.876 किलो गांजा जब्त किया। उसकी कीमती करीब 2.93 लाख रुपए आंकी गई। नेवई पुलिस ने रिसाली सेक्टर भिलाई स्थित ब्लॉक-298 एल के सामने एक संदिग्ध को पकड़ा। आरोपी कविराज लीमा (45 वर्ष) के कब्जे से 1.75 लाख कीमत का 3.554 किग्रा गांजा मिला। उतई थाना पुलिस ने ग्राम पतोरा तालाब पार के पास से बाइक सवार कविराज लीमा (45 वर्ष) को पकड़ा। दोनों गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। दोनों के पास से 1.50 लाख कीमत का 2.975 किग्रा गांजा बरामद किया गया। प्रकरण से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पतासाजी की जा रही है।

नाम परिवर्तन

ANNAPURNA AGRAWAL W/O RAJIV AGRAWAL निवासी - बी 79. अमरापाली वानंचल सिटी गौरव पथ रोड नियर हाउसिंग बोर्ड भिलाई तह. व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ, जो कि निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों मेरे स्वयं का नाम में मेरा नाम ANNPURNA AGGARWAL दर्ज है। मेरे स्वयं के नाम से जारी आधार कार्य क्रमांक-8321 0286 8264 में मेरा नाम ANNAPURNA AGRAWAL दर्ज है जो कि सही एवं सत्य है। ANNAPURNA AGRAWAL एवं ANNPURNA AGGARWAL ये दोनों ही नाम अलग अलग है किन्तु ये दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे स्वयं का ही नाम है जो कि सही सत्य है। भविष्य में मेरे नाम से शासकीय अशासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेज बनाये जाएगा मेरा नाम हिन्दी में तथा अंग्रेजी में ANNAPURNA AGRAWALही होगा। यह कि यह शपथ पत्र सार्वजनिक समाचार पत्र प्रकाशन के सक्षम प्राधिकारी के समझ मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे स्वयं का नाम ANNAPURNA AGRAWAL दर्ज किये जाने के संबंध में प्रस्तुत कर रही हूं।

अन्नपूर्णा अग्रवाल

Name Change

PRAMOD KUMAR SAHU son of Shri. DAYALU RAM SAHU, Aged about 28 Years, Resident of House No. 128, Gali No. 5, Gautam Nagar Ward No. 04, Supela, Bhilai, Dist. Durg, Chhattisgarh-490023, do hereby declare that My name in Aadhar Card-685061769933 & PAN-LHKPS7273P is mentioned as "PRAMOD KUMAR SAHU". That in my 10th, 12th & College certificate my name is mentioned as "PRAMOD KUMAR". That both the above names "PRAMOD KUMAR SAHU" & "PRAMOD KUMAR" belong to same person i.e me only and correct name is "PRAMOD KUMAR SAHU". That I am producing these affidavit in support to Bank Documents, Job purpose & Future. Documentation purpose.

PRAMOD KUMAR
Gautam Nagar Ward No. 04,
Supela

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
सामान्य वनमण्डल दुर्ग
पुलगांव डिपो का ई-ऑक्शन का संक्षिप्त विज्ञापन

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दुर्ग वनमण्डल के अधिनस्थ शासकीय उपभोक्ता डिपो पुलगांव, अण्डा, सुपेला, पाटन, वन परिसर कुम्हारी, बेमेतरा, एवं अन्य डिपो में संग्रहित ईमारती काष्ठ, जलाऊ एवं बल्ली का ई-ऑक्शन द्वारा निर्वतन निम्नानुसार किया जावेगा। इच्छुक बोलीदारों से अनुरोध है, कि वे ई-ऑक्शन में भाग लेवें। ई-ऑक्शन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय/संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। ई-ऑक्शन में रखे जाने वाले अनुमानित मात्रा :-

नीलाम तिथि - 27/03/2026
समय - प्रातः 9.00 बजे

नया ईमारती काष्ठ/जलाऊ चट्टा

परिक्षेत्र	डिपो	प्रजाति	लट्ठा घ.मी.	चिरान	बल्ली नग	डेंगरी	जलाऊ चट्टा
दुर्ग	पाटन	कहुआ लट्ठा/मिश्रित लट्ठा	6.663	-	-	-	-
	सुपेला	मिश्रित लट्ठा/मिश्रित जलाऊ	17.507	-	-	-	33
	अण्डा	मिश्रित लट्ठा	2.312	-	-	-	-
धमधा	धमधा	कहुआ लट्ठा/सोफा फ्रेम, बत्ता चिरान/मि. ज.	1.716	0.304	-	-	3
साजा	साजा	सागौन लट्ठा/बल्ली/डेंगरी	14.736		110	23	-
		योग :-	42.934	0.304	110	23	36

अविक्रित काष्ठ/जलाऊ चट्टा

परिक्षेत्र	डिपो	प्रजाति	लट्ठा (घ.मी.	चिरान घ.मी.	बल्ली/डेंगरी नग	जलाऊ घ.
दुर्ग	पुलगांव	सागौन लट्ठा/बल्ली/डेंगरी	525.392	-	25362/20722	6
-,,-	-,,-	आम/मिश्रित लट्ठा	4.563	-	-	-
-,,-	पाटन	सागौन लट्ठा, बल्ली, डेंगरी/साल चिरान	3.476	2.185	203/745	38
-,,-	सुपेला	सागौन लट्ठा, नीलगिरी लट्ठा	1.277	-	-	-
धमधा	धमधा/कुम्हारी	सागौन लट्ठा, डें./मिश्रित जलाऊ	3.582	-	/22	4
बेमेतरा	बेमेतरा	सागौन लट्ठा	18.462	-	-	-
		योग :-	556.752	2.185	25565/21489	48

टीप :-
(1) क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व एम.एस.टी.सी. ई-कामर्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
(2) क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व क्रय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखवना अनिवार्य है। सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई.एम.डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
(3) लॉट की थप्पी सूची एवं फोटो एम.एस.टी.सी. ई-कामर्स पोर्टल में अपने आईडी से लॉग-इन करके देख सकते है।।
(4) ई-ऑक्सन में लॉट क्रय के पश्चात् प्रथम क्रेता को 40 सेकंड का समय प्राप्त होगा उसी लॉट में अन्य क्रेताओ द्वारा 40 सेकंड के पूर्व क्रय करने पर 30 सेकंड का समय प्राप्त होगा।
(5) सफल क्रेताओं को अपना पूर्ण पता, मो.नं., पैन कार्ड एवं GST की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

फोन नं. - 75870-13100, ई-मेल: dfodurg@gmail.com

वनमण्डलाधिकारी
दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग (छ.ग.)

जी - 252607311/6

दुल्हन को लेकर लौट रही गाड़ी पलटी, बच्ची की मौत

कोरबा। कोरबा जिले में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र में शादी से लौट रही दुल्हन की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। घटना डबरीपारा मोड़ के पास की बताई जा रही है। वाहन ग्राम कसरेंगा से कोरबा के दादर खुर्द की ओर जा रहा था। गाड़ी में दुल्हन सहित महिलाएं और बच्चे समेत कुल 11 लोग सवार थे। इसी दौरान अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घटना में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल 10 लोगों का इलाज बांकी मोंगरा स्थित एसईसीएल अस्पताल में जारी है।

खास खबर

विधायक भावना ने उठाया सरकारी स्कूलों का मुद्दा

कवर्धा। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में स्कूल शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सदन के समक्ष रखा। उन्होंने शासकीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति, बालिकाओं के लिए शौचालय, शिक्षकों की कमी और छात्र-छात्राओं के मूलभूत सुविधाओं सहित परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के सन्दर्भ में प्रश्न किया। उन्होंने शासकीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति, बालिकाओं के लिए शौचालय, शिक्षकों की कमी और छात्र-छात्राओं के मूलभूत सुविधाओं सहित परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के सन्दर्भ में प्रश्न किया।

खुले में अंतिम संस्कार की मजबूरी होगी खत्म, 9 मुक्तिधाम स्वीकृत

बिलासपुर। खुले में दाह संस्कार की मजबूरी अब खत्म हो जाएगी। नगर निगम ने 4.45 करोड़ रुपए का विकास प्रस्ताव शासन को भेजा है। मंजूरी मिलते ही नौ मुक्तिधामों में शेड, प्लेटफॉर्म, पेवर ब्लॉक, पेयजल, लाइट और बाउंड्रीवॉल जैसे काम शुरू किए जाएंगे। अलग-अलग वार्डों और आउटर क्षेत्रों में स्थित मुक्तिधामों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। कई मुक्तिधामों में लंबे समय से शेड, बैठने की व्यवस्था, पानी, रोशनी और पक्के रास्तों जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को परेशानी होती है।

बस्तर राइडर्स मीट : पहुंचेंगे देशभर के राइडर्स

जगदलपुर। 4 अप्रैल 2026 को 'गरुड़ा द राइडर्स क्लब' की तरफ से बस्तर राइडर्स मीट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से बाइक राइडर्स और राइडिंग के शौकीन लोग हिस्सा लेंगे। आयोजन का उद्देश्य बस्तर की समृद्ध संस्कृति, खानपान और वेशभूषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। राइडर्स को बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों से रूबरू कराया जाएगा।

बस्तर हेरिटेज मैराथन-2026 : कल बस्तर की वादियों में गूंजेगी केन्या और इथोपिया के धावकों के कदमों की धमक

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कल 22 मार्च को आयोजित होने वाली 'बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026' केवल एक क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं और स्थानीय संस्कृति का एक भव्य संगम बनने जा रही है। इस वर्ष के आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता विदेशी धावकों की भागीदारी है, जो बस्तर की सड़कों पर अपनी रफ्तार का जलवा बिखेरेंगे। अब तक हुए 5000 से अधिक कुल पंजीकरणों में 68 विदेशी धावकों का शामिल होना इस बात का प्रमाण है। विशेष रूप से लंबी दूरी की दौड़ के लिए दुनिया भर में मशहूर इथोपिया के 42 और केन्या के 26 मंझे हुए एथलीट्स की मौजूदगी ने इस मुकाबले को बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

इस महाकुंभ का मुख्य आकर्षण 42 किलोमीटर की 'फुल मैराथन' होगी। यह ऐतिहासिक सफर जगदलपुर के लालबाग मैदान से शुरू होकर 'भारत के नियाग्रा' कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात के तट पर संपन्न होगा। धावक जब बस्तर के पारंपरिक गांवों और नैसर्गिक सौंदर्य के बीच से गुजरेंगे, तो उन्हें यहाँ की समृद्ध विरासत और अदम्य साहस का जीवंत अनुभव होगा।

बस्तर हेरिटेज मैराथन को फुल मैराथन, हाफ मैराथन (21 किमी), 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की श्रेणियों में विभाजित किया है। 25 लाख रुपये की विशाल इनामी राशि की घोषणा की गई है। इसमें 'ओपन कैटेगरी' के साथ-साथ विशेष रूप से 'बस्तर कैटेगरी' को भी शामिल किया गया है, ताकि स्थानीय धावकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपनी प्रतिभा निखारने का एक सुनहरा अवसर मिल सके। स्थानीय समुदाय की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बस्तर जिले के सभी धावकों हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णत: निःशुल्क रखी गई है। बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने विदेशी मेहमानों और अन्य क्षेत्रों के धावकों का स्वागत करते हुए सभी से अपील की है कि वे आधिकारिक वेबसाइट bastarheritage.run या हेल्पलाइन नंबर +91-92440-79533 के माध्यम से इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बनें। यह मैराथन न केवल खेल भावना को बढ़ावा देगी, बल्कि विश्व पटल पर बस्तर की एक नई, शांतिप्रिय और साहसी छवि को भी मजबूती से प्रस्तुत करेगी।

डबल इंजन सरकार ने खत्म किया नक्सलवाद, खुल गया विकास का रास्ता

■ नेशनल डिफेंस कॉलेज का 15 सदस्यीय दल 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा है छत्तीसगढ़

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की हमारी धरती सघन वन, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा के विपुल भंडार, लोक संस्कृति की अमूल्य विरासत और नैसर्गिक सौन्दर्य का अद्भुत संगम है। इस सुंदर धरती के विकास की सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद को हमारे डबल इंजन की सरकार ने अब दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में नेशनल डिफेंस कॉलेज के सैन्य एवं सिविल सेवा अधिकारियों के अध्ययन दल से मुलाकात कर आत्मीय संवाद किया।

अध्ययन दल का नेतृत्व कर रहे एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी ने छत्तीसगढ़ प्रवास के अनुभव साझा करते हुए राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विशेषताओं की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सघन वनों, खनिज संपदा, समृद्ध लोक संस्कृति और नैसर्गिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम है। राज्य का लगभग 46 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है, जिसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान और कैम्पा योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री साय ने कहा कि राज्य खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है—कोयले से लेकर हीरे तक यहां उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस राज्य है, जहां लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। पिछले दो वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिससे अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विकसित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से अब नक्सल समस्या समाप्ति की ओर है। इससे शांति और विकास की गति तेज होगी।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहां किसानों के लिए प्रभावी धान खरीदी नीति लागू है। 'महतारी वंदन योजना' का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके तहत 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को प्रदान की जा चुकी है। 5 लाख 30 हजार से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।

अध्ययन दल में शामिल विदेश के सैन्य अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ प्रवास को अद्भुत और यादगार बताया।

एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्पष्ट नेतृत्व और सशक्त नीति के कारण प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सुरक्षाबलों का मनोबल बढ़ा है जिससे नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्य हुआ है।

इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, आईजी ओपी पाल, अध्ययन दल में आईपीएस अमनदीप सिंह कपूर, म्यांमार कर्नल लू जॉ आंग, ब्रिगेडियर मोहम्मद शाहिद अहमद, जापान के कर्नल उचीनो तोमोफुमी, ब्रिगेडियर कुंवर मान विजय सिंह राणा, सुप्रिया घाघ, ब्रिगेडियर शिशिर थमैय्या, बांग्लादेश के ब्रिगेडियर जनरल फिरदौस आरिफ अहमद, ब्रिगेडियर केतन अरुण मोहिते, ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान, एयर कमोडोर श्री अजय कुमार चौधरी, एयर कमोडोर मूलनाथ गिरीश, डॉ. राजेश कुमार अस्थाना, भूटान के कर्नल समतेन चेनोर, ग्रीस के कर्नल कॉन्सटेंटिनॉस नीरस शामिल है।

उल्लेखनीय है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा प्रतिवर्ष एक साल का कोर्स आयोजित किया जाता है।

माई दंतेश्वरी को 23 मार्च को चढ़ाई जाएगी 108 मीटर लंबी चुनरी

जगदलपुर। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि के प्रारंभ से लेकर प्रभु श्री राम के जन्म नवमी एवं श्री हनुमान के प्रकटोत्सव तक विश्व हिंदू परिषद राम जन्म उत्सव समिति द्वारा जिले भर में भव्य एवं उल्लासपूर्वक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम नगर एवं ग्रामों में आयोजित किये जाएंगे।

सीताराम शिवालय में हुई समाज प्रमुखों एवं प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक में पखवाड़े भर के कार्यक्रम सुनिश्चित किये गये जिसका सभी ने ध्वनिमत से समर्थन किया इसके अनुसार नगर में 23 मार्च दिन सोमवार को मातृ शक्ति एवं दुर्गा वाहिनी द्वारा 108 मीटर लंबी विशाल चुनरी यात्रा सीताराम शिवालय से प्रारंभ होकर मां दंतेश्वरी मंदिर में माता को चुनरी समर्पित करके संपन्न होगी। जबकि 25 को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा विशाल आमंत्रण बाइक रैली दोपहर 2.30 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर से प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर के सभी वार्डों में भ्रमण करते हुए मां दंतेश्वरी के प्रांगण में ही संपन्न होगी। यह रैली नगर के सभी नागरिकों को श्री राम जन्म उत्सव कार्यक्रम को भव्य और उत्साह के साथ मनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए होगी। यह बात विहिप योगेंद्र कौशिक ने कही। शुक्रवार को प्रभु श्री राम जी के प्रकटोत्सव को भव्य एवं विशाल रूप से मनाने के लिए दोपहर 3 बजे मां दंतेश्वरी के प्रांगण में सभी सनातनी एकत्रित होंगे।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स : बस्तरवासियों को देखने मिलेंगे एथलेटिक्स के रोमांचक मुकाबले

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तहत बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के धरमपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर में एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। देश में पहली बार हो रहे राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं। प्रतियोगिता स्थल धरमपुरा क्रीड़ा परिसर में ट्रैक, मैदान, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही लाइटिंग, सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल एवं आवास जैसी व्यवस्थाओं को भी प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए देशभर के जन-जातीय खिलाड़ी बड़ी संख्या में बस्तर पहुंचेंगे। इस आयोजन में न केवल अंचल के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक विविधता को भी राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

बस्तर जिला प्रशासन और खेल विभाग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। पूरी प्रतियोगिता के दौरान स्थानीय खेलप्रेमियों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।

प्लास्टिक कचरे से चमकेंगी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें, लगा मिक्सिंग प्लांट

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्लास्टिक कचरे (वेस्ट) का उपयोग कर टिकाऊ और मजबूत सड़कें बनाई जा रही हैं। इसमें डामर के साथ 8 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा मिलाकर उपयोग किया जाता है, जिससे सड़कों की मजबूती और सर्विस लाइफ बढ़ती है, साथ ही यह पर्यावरण को भी स्वच्छ रखता है।

छत्तीसगढ के सरगुजा जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन की दिशा में नवाचार किया गया है। जिले में अब प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए किया जा रहा है। इस नवाचार के तहत मैनपाट क्षेत्र में पहली ऐसी प्रयोगात्मक सड़क का निर्माण किया गया है, जिसमें बिटुमिन (डामर) के साथ प्लास्टिक कचरे का मिश्रण किया जा रहा है।

बतौली विकासखंड के सुवारपारा में स्थित प्लांट में गिट्टी और डामर के मिश्रण में प्लास्टिक वेस्ट मिलाया जा रहा है, ये प्लास्टिक वेस्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो रहे कचरा कलेक्शन से इकट्ठा हुए प्लास्टिक को दरिमा स्थित एसआरएफ सेंटर से पीएमजी एसवाई विभाग द्वारा खरीदा जाता है और सडक निर्माण में लगे ठेकेदार इसका उपयोग सडक निर्माण में कर रहे हैं।

प्लास्टिक वेस्ट कभी शहर और पर्यावरण के लिए एक मुसीबत हुआ करता था आज वही कचरा कमाई का साधन बन चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत काम कर रही समूह की महिलाये इस वेस्ट से पैसे कमा रही हैं। प्लास्टिक वेस्ट को पहले बाजार में 15 से 20 रुपये किलो का ही रेट मिल पाता था, लेकिन जिला प्रशासन के प्रयास से सडक निर्माण के लिए इस प्लास्टिक वेस्ट को 25 रुपये किलो खरीदा जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के ईई बताते हैं की इसमें अभी वेस्ट प्लास्टिक का यूज़ नवाचार के रूप में कर रहे हैं, जो डामरीकरण की ओजीपीसी की लेयर होती है उसमें 8 प्रतिशत जो डामर का वेट होता है उसके आधार पर हम उसमें वेस्ट प्लास्टिक मिक्स करते हैं और उसको सड़क में यूज करते हैं।

अबुझमाड़ के युवाओं ने अनुभव की लोकतंत्र की कार्यप्रणाली; डिप्टी सीएम से किया संवाद

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नारायणपुर जिले के सुदूर संवेदनशील एवं पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आए अबुझमाड़िया युवाओं ने नया रायपुर स्थित नवीन विधानसभा में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। लोकतंत्र के इस जीवंत मंदिर में पहुंचकर युवाओं ने शासन-प्रशासन की विधायी कार्यप्रणाली को करीब से समझा और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अनुभव किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं वनमंत्री केदार कश्यप ने इन युवाओं से मुलाकात की।

स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आयोजित इस भ्रमण में नारायणपुर के कुतुल, ओरछा, कलमानार, झारावाही, कोडकानार, मुरेहनार, गुमियाबेड़ा, मुरहानार और नेडनार जैसे अति संवेदनशील क्षेत्रों से आए विशेष पिछड़ी जनजाति के अबूझमाड़िया समुदाय के लगभग 147 युवा शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इन युवाओं में से अधिकांश ने पहली बार रायपुर शहर का भ्रमण किया, जो उनके लिए एक नया और उत्साहजनक अनुभव रहा।

विधानसभा पहुंचकर युवाओं ने प्रश्नकाल, चर्चा और निर्णय प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा, जिससे उनके भीतर लोकतंत्र के प्रति समझ और जागरूकता का विस्तार हुआ। उन्हें विधायी प्रक्रिया, शासन व्यवस्था और जनहित में लिए जाने वाले निर्णयों की विस्तृत जानकारी भी दी गई।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने युवाओं से आत्मीय मुलाकात कर संवाद किया। उन्होंने युवाओं के अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, जागरूकता और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि अति संवेदनशील क्षेत्रों से निकलकर नई सोच और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे ये युवा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के प्रतीक हैं। उन्होंने युवाओं से नक्सलवाद के खात्मे के साथ हो रहे विकास पर उनके अनुभवों को जाना। उन्होंने सभी को स्वसहायता समूहों एवं सहकारी समितियों से जुड़कर स्थानीय रूप से उत्पादित लघु वनोपजों का प्रसंस्करण एवं संवर्धन कर आजीविका के माध्यम बढ़ाने को प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

वन मंत्री एवं नारायणपुर के स्थानीय विधायक केदार कश्यप ने भी अपने क्षेत्र के युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने सभी के भ्रमण के अनुभवों की जानकारी ली। उन्होंने सभी से उनके क्षेत्र में विकास और सुविधाओं की जानकारी भी ली। युवाओं ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए इसे जीवन का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी अवसर बताया।

दिग्विजय कॉलेज के विद्यार्थी पहुंचे लोकभवन : किया संवाद

रायपुर (लोकभवन)। राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर 'लोकभवन' की गतिविधियों से जनसामान्य को जोड़ने लोकभवन का भ्रमण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वाशासी महाविद्यालय राजनांदगांव के विद्यार्थियों ने लोकभवन का भ्रमण किया। बीए और एमए के विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था और लोक भवन की ऐतिहासिक व कार्यालयीन महत्ता को जाना और समझा। इससे पहले स्कूली विद्यार्थी और गोद ग्राम के ग्रामीणों ने लोकभवन का भ्रमण किया था। उन्हें लोकभवन परिसर स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम, उदंती परिसर, कन्हार परिसर, डिस्पेंसरी, सचिवालय की विभिन्न शाखाओं और हरे-भरे उद्यान का भ्रमण कराया गया और इन स्थानों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई।

ई चालान जमा करने ओटीसी एक अप्रैल से

कोंडागांव। भौतिक चालानों का प्रचलन समाप्त किए जाने एवं ऑनलाइन माध्यम से ही चालान जमा किए जाने हेतु ओटीसी (ओवर द काउंटर) की सुविधा 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारी चालान जमाकर्ताओं को ई चालान जमा करने की प्रक्रिया से अवगत कराने तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

भर्ती परीक्षा के लिए और सख्त हुआ कानून; मिलेगी सख्त सजा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 को पारित किया दिया। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में आयोजित होने वाली भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित राज्य के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में अनुचित साधनों के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करना और योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्नपत्र लीक, फर्जी अभ्यर्थियों की भागीदारी तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से नकल जैसी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में 3 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि संगठित अपराध के मामलों में एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने के साथ संपत्ति जब्ती का भी प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी नकल या अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे एक से तीन वर्ष तक परीक्षा से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि परीक्षा से जुड़ी एजेंसियों, आईटी सेवा प्रदाताओं और परीक्षा केंद्रों के प्रबंधकों को भी जवाबदेह बनाया गया है। ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता की संभावना को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस कानून के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा से संबंधित मामलों की जांच उप निरीक्षक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, जिससे जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहे। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार विशेष जांच एजेंसियों को भी जांच सौंप सकेगी।

उन्होंने बताया कि यह कानून राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापमं तथा विभिन्न शासकीय विभागों, निगमों और मंडलों द्वारा आयोजित सभी भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा। इसके माध्यम से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने, अनुचित हस्तक्षेप को रोकने और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950